बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 12 ● नई दिल्ली ● शुक्रवार 17 अक्तूबर 2025 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

तेलंगाना सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, ओबीसी को 42 प्रतिशत आरक्षण पर रोक का फैसला बरकरार

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें राज्य सरकार ने ओबीसी वर्ग को स्थानीय निकाय चुनाव में 42 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग की थी। इससे पहले तेलंगाना हाईकोर्ट ने भी राज्य सरकार के इस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट के अंतरिम फैसले के खिलाफ तेलंगाना सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट से भी उसे निराशा हाथ लगी है और सर्वोच्च अदालत ने याचिका खारिज कर दी। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने राज्य सरकार की विशेष याचिका खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि उच्च न्यायालय को मेरिट के आधार पर फैसला करना चाहिए और उसे राज्य सरकार की याचिका खारिज होने से प्रभावित नहीं होना चाहिए।

यमुना नदी में आया काफी सुधार, सीएम रेखा गुप्ता ने बताया- ऑक्सीजन बढ़ी, झाग और अमोनिया कम

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि राजधानी में यमुना की सफाई को लेकर विपक्ष के आरोप पूरी तरह झूठे और भ्रामक हैं. उन्होंने कहा कि कालिंदी कुंज घाट पर दिल्ली सरकार ने बाकायदा एक आधुनिक प्रयोगशाला (लैब) स्थापित की है, जो हर दिन यमुना के पानी की जांच कर रही है. इस जांच में साफ दिख रहा है कि पिछले कुछ महीनों में यमुना की स्थिति में बड़ा सुधार हुआ है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि ताज़ा जांच के अनुसार, यमुना के पानी में ऑक्सीजन लेवल अब 4.75 तक पहुंच गया है. इसका मतलब है कि अब नदी के अंदर जल जीव-जंतु (जैसे मछलियां और अन्य जीव) जिंदा रह सकते हैं. उन्होंने कहा कि पहले यमुना की हालत इतनी खराब थी कि पानी में जीवन का कोई निशान नहीं था, लेकिन अब हालात तेजी से बदल रहे हैं.

मुख्यमंत्री ने बताया कि अब पानी में अमोनिया की मात्रा काफी कम हो गई है. पहले जहां यमुना के पानी में झाग बनता था, वहीं अब फास्फेट का स्तर घटकर सिर्फ 0.2 रह गया है, जिससे झाग बनना लगभग बंद हो गया है. यह सब दिल्ली सरकार और दिल्ली जलबोर्ड के लगातार प्रयासों का नतीजा है, उन्होंने कहा. रेखा गुप्ता ने कहा कि यह सुधार केवल दावा नहीं, बल्कि लैब टेस्टिंग से साबित हुआ है. वैज्ञानिक आंकड़े बता रहे हैं कि सरकार के कदमों का असर साफ दिखाई दे रहा है. रोजाना यमुना की स्थिति में सुधार हो रहा है और जल्द ही लोग एक साफ-सुथरी, अविरल यमुना को देख सकेंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहली बार है जब किसी सरकार ने यमुना की सफाई के लिए जमीनी स्तर पर लगातार काम किया है.

उन्होंने कहा कि आने वाले छठ पर्व के दौरान श्रद्धालु स्वच्छ और बहती यमुना में सूर्य देव को अर्घ्य दे सकेंगे जो अपने आप में एक ऐतिहासिक बदलाव होगा. मुख्यमंत्री ने जनता से अपील की कि वे दिल्ली सरकार के इस प्रयास का हिस्सा बनें और यमुना में गंदगी न फैलाएं. यह सिर्फ सरकार की नहीं बल्कि पूरे दिल्लीवासियों की जिम्मेदारी है कि हम अपनी नदी को जीवंत बनाए रखें.

निमिषा प्रिया को फांसी होगी या नहीं? सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने दिया ताजा अपडेट

नई दिल्ली। यमन में हत्या के आरोप में फांसी की सजा पाने वाली भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की फांसी पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि इस मामले में एक नया मध्यस्थ सामने आया है और स्थिति अभी स्थिर है। 38 वर्षीय निमिषा केरल के पलक्कड़ की रहने वाली हैं। 2017 में अपने यमनी बिजनेस पार्टनर की हत्या के मामले में दोषी ठहराई गई थीं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने बताया कि निमिषा की फांसी पर रोक है और कोई प्रतिकूल घटना नहीं हुई है। निमिषा को बचाने के लिए याचिका दायर करने वाली संस्था सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल के वकील ने भी इसकी पुष्टि की। अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट को सूचित किया कि मामले में एक नया मध्यस्थ सामने आया है, जो संभवतः बातचीत को आगे बढ़ा सकता है। याचिकाकर्ता के वकील ने सुझाव दिया कि मामले को स्थगित किया जाए, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। बेंच ने कहा कि मामला जनवरी 2026 में सुना जाएगा, लेकिन यदि स्थिति की मांग हुई तो जल्दी सुनवाई के लिए आवेदन किया जा सकता है। निमिषा को 2017 में दोषी ठहराया गया था, 2020 में फांसी की सजा सुनाई गई और 2023 में उनकी अंतिम अपील खारिज हो गई थी। वह वर्तमान में यमन की राजधानी सना के जेल में बंद है। भारत सरकार ने जुलाई में कहा था कि वह यमनी अधिकारियों और कुछ मित्र देशों के साथ संपर्क में है ताकि पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान निकाला जा सके। याचिकाकर्ता के वकील ने पहले कोर्ट को बताया था कि शरिया कानून के तहत पीड़ित के परिवार को ब्लड मनी का भुगतान कर निमिषा को माफी दिलाने की संभावना तलाशी जा सकती है। उन्होंने कहा कि यदि पीड़ित का परिवार ब्लड मनी स्वीकार कर ले, तो वह निमिषा को माफ कर सकता है। निमिषा की मां यमन में पीड़ित के परिवार से बातचीत करने गई थीं, जिसके लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र को उनकी यात्रा की अनुमति देने का निर्देश दिया था। 14 अगस्त को, याचिकाकर्ता के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया था कि निमिषा को तत्काल कोई खतरा नहीं है। केंद्र सरकार ने भी 18 जुलाई को कोर्ट को आश्वासन दिया था कि वह निमिषा को सुरक्षित निकालने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। यह मामला न केवल निमिषा के जीवन से जुड़ा है, बल्कि भारत-यमन के राजनयिक संबंधों और मानवीय आधार पर सहानुभूति का भी प्रतीक है।

भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर का दुनिया ने देखा पराक्रम, राजनाथ बोले- यह आत्मनिर्भरता का सबूत

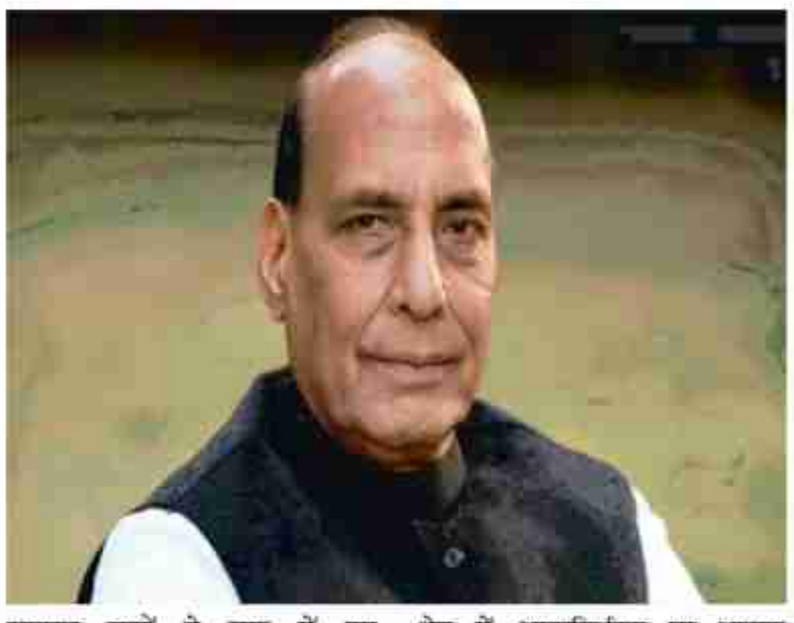

नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की आत्मनिर्भरता का जीता जागता सबूत है। उन्होंने ऑपरेशन के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता की सराहना की। पुणे में सिम्बायोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए, राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अपने आप में हमारी आत्मनिर्भरता का जीता जागता सबूत है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, हमारे सशस्त्र बलों द्वारा प्रदर्शित वीरता को पूरी दुनिया ने देखा। खास बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, हमारे बलों ने बड़ी मात्रा में भारत में निर्मित उपकरणों का इस्तेमाल किया। ऑपरेशन सिंदूर 7 मई को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए एक आतंकी हमले के बाद शुरू किया गया था, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओजेके) में आतंकवादी ढाँचे पर हमला किया। भारतीय सशस्त्र बलों ने बाद में हुए पाकिस्तानी आक्रमण को भी प्रभावी ढंग से विफल किया और उसके हवाई ठिकानों पर बमबारी की। भारत की कड़ी प्रतिक्रिया के बाद, पाकिस्तानी डीजीएमओ ने शत्रुता समाप्त करने के लिए अपने भारतीय समकक्ष से संपर्क किया। इसके अतिरिक्त, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी भारतीय रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर भाजपा सरकार के फोकस पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से रक्षा क्षेत्र में जो स्थितियाँ थीं, हमने उन्हें बदल दिया है। हमने इस बात पर ज़ोर दिया कि भारत अपने सैनिकों के लिए देश में ही हथियार बनाएगा। हमारे लिए परिस्थितियाँ बहुत प्रतिकूल थीं। लेकिन हमने हार नहीं मानी। हमने रक्षा निर्माण को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास किया। और हमें अपने प्रयासों के सकारात्मक परिणाम दिखने लगे। राजनाथ सिंह ने युवाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्किल इंडिया और स्टार्ट-अप इंडिया पहल पर भी प्रकाश डाला। राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी आत्मनिर्भर भारत के अपने दृष्टिकोण को समझते हैं और उसे साकार करते हैं, इसलिए युवाओं के कौशल को बढ़ाना आवश्यक है, उन्होंने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की स्थापना पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, 2014 से, जब देश ने न्यू इंडिया की ओर कदम बढ़ाए, प्रधानमंत्री ने बार-बार स्किल इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया और मेक इन इंडिया के बारे में बात की है, क्योंकि उन्होंने समझा कि अगर भारत को आत्मनिर्भर बनना है, तो सबसे पहले युवाओं को कुशल बनाना होगा। जैसे ही हम सत्ता में आए, हमने कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित मंत्रालय की स्थापना की।

सीजेआई पर जूता फेंकने की घटना में आरोपी वकील के खिलाफ होगी अवमानना कार्रवाई

नई दिल्ली। अटॉर्नी जनरल (एजी) ने भारत के प्रधान न्यायाधीश बी. आर. गवई पर जूता फेंकने का प्रयास करने वाले वकील के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू करने की सहमति दे दी है। बृहस्पतिवार को उच्चतम न्यायालय को इस बारे में सूचित किया गया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) के प्रमुख एवं वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जे. बागची की पीठ से अनुरोध किया कि प्रधान न्यायाधीश पर जूता फेंकने वाले वकील राकेश किशोर के खिलाफ अवमानना मामले की सुनवाई की जाए।

सिंह ने कहा कि छह अक्टूबर को हुई इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर अनगिनत सामग्री प्रसारित हुई है, जो संस्थागत अखंडता और गरिमा को ठेस पहुंचा रही है। मेहता और सिंह ने अदालत से सोशल मीडिया पर ऐसी सामग्री पोस्ट करने पर रोक से संबंधी आदेश पारित करने का अनुरोध करते हुए कहा कि हर तरह की अपमानजनक टिप्पणियां की जा रही हैं। पीठ ने कहा कि भाषण और अभिव्यक्ति का मौलिक अधिकार दूसरों की गरिमा की कीमत पर नहीं हो सकता है। इसने सोशल मीडिया की ''अनियमित प्रकृति के दुष्प्रभावों की ओर इशारा किया और कहा, ''हम सामग्री के उत्पाद और उपभोक्ता दोनों हैं। प्रधान न्यायाधीश पर जूता फेंकने के प्रयास की यह अभूतपूर्व घटना छह अक्टूबर को हुई। उस दिन सुबह करीब 11:35 बजे अदालत कक्ष संख्या-एक में 71-वर्षीय अधिवक्ता राकेश किशोर ने अपने जूते उतारकर उन्हें प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ की ओर फेंकने का प्रयास किया। सुरक्षाकर्मियों ने आरोपी अधिवक्ता को तुरंत हिरासत में ले लिया। अदालती कार्यवाही के दौरान हुई इस घटना से अविचलित प्रधान न्यायाधीश ने अदालत के अधिकारियों और अदालत कक्ष में मौजूद सुरक्षाकर्मियों से इसे नजरअंदाज करने और राकेश किशोर नामक दोषी वकील को चेतावनी देकर छोड़ देने को कहा।

दिल्ली में पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत पर दिल्ली सरकार ने लगाए नए नियम, मिलेगी सीमित अनुमति!

नई दिल्ली । दिवाली से पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों की बिक्री और उपयोग की अनुमति दिए जाने के फैसले ने कारोबारियों और नागरिकों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है. पर्यावरण संरक्षण और परंपरा के बीच संतुलन बनाते इस निर्णय को लेकर व्यापार जगत ने खुशी जाहिर की है. बाजारों में अब फिर से रौनक लौटने की उम्मीद जताई जा रही है सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली में ग्रीन पटाखों पर आंशिक राहत दिए जाने के बाद दिल्ली सरकार ने तुरंत एक्शन में आकर तैयारी शुरू कर दी है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अपील और पहल पर कोर्ट ने सीमित समय में ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी है. इस फैसले के बाद पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने सभी एजेंसियों और पटाखा विक्रेताओं के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें कीं, ताकि आदेश का पालन सख्ती से कराया जा सके. बैठक में दिल्ली पुलिस, DPCC, MCD, NDMC, NEERI, PESO और जिला अधिकारियों के अलावा खुद मंत्री सिरसा मौजूद रहे. उन्होंने पटाखा विक्रेताओं से कहा कि वे केवल वही ग्रीन पटाखे बेचें जिन पर NEERI द्वारा प्रमाणित क्यूआर कोड लगा हो. बिक्री की अनुमति केवल 18 से 20 अक्टूबर तक रहेगी और जलाने की अनुमति 19 व 20 अक्टूबर को सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक ही दी गई है. मंत्री सिरसा ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने हमें यह छूट दी है, लेकिन यह जिम्मेदारी के साथ आई है. अगर हम सभी नियमों का पालन करेंगे, तो यह अस्थायी राहत भविष्य में स्थायी व्यवस्था बन सकती है. उन्होंने कहा कि पटाखा विक्रेता भी जागरूकता अभियान में साझेदार बनें और लोगों को बताएं कि ग्रीन पटाखे पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाते हैं. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कोर्ट से अपील की थी कि दिल्लीवासियों की भावनाओं का सम्मान करते हुए सीमित समय में प्रमाणित ग्रीन पटाखों की अनुमति दी जाए. उन्होंने कहा था कि सरकार पर्यावरण और परंपरा, दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना चाहती है. दिल्ली सरकार अब DPCC के जरिए 14 से 25 अक्टूबर तक वायु गुणवत्ता सूचकांक की निगरानी करेगी और हर दिन की रिपोर्ट CPCB व सुप्रीम कोर्ट को भेजेगी. दिल्ली पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि वे अस्थायी बिक्री लाइसेंस दो दिन के भीतर जारी करें ताकि तैयारियों में देरी न हो. दिवाली के बाद दो दिन का समय विक्रेताओं को बचा हुआ स्टॉक वापस करने या नष्ट करने के लिए दिया जाएगा. मंत्री सिरसा ने कहा, दिल्ली के लोगों ने परंपरागत तरीके से दिवाली मनाने की मांग की थी. अब जब कोर्ट ने अनुमति दी है, तो हमें जिम्मेदारी भी निभानी होगी.आइए, इस बार खुशियों के साथ प्रदूषण-मुक्त और अनुशासित दिवाली मनाएं.

ग्रीन पटाखों की मंजूरी से बढ़ी बाजार में रौनक - परमजीत सिंह पम्मा

सदर बाजार बारी मार्केट के अध्यक्ष परमजीत सिंह पम्मा ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह निर्णय न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि त्योहारों की खुशियों को भी बनाए रखेगा. उन्होंने कहा, ग्रीन पटाखे पर्यावरण अनुकूल हैं और ये त्योहारों को रंगीन बनाते हैं. इससे न सिर्फ शहर स्वच्छ रहेगा बल्कि त्योहारों की चमक भी बरकरार रहेगी. पम्मा ने आगे कहा कि दिवाली रोशनी, मिठाई और पटाखों के बिना अधूरी है. अब जब ग्रीन पटाखों की अनुमति मिल गई है, तो बाजारों में खरीदारों की भीड़ और बढ़ेगी और दिवाली का त्योहार पहले से ज्यादा धूमधाम से मनाया जाएगा.

सीएम का कदम सराहनीय- सांसद प्रवीन खंडेलवाल

सांसद प्रवीन खंडेलवाल ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की पहल की सराहना की, जिन्होंने ग्रीन पटाखों की अनुमति के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. खंडेलवाल ने कहा, मुख्यमंत्री का यह कदम हमारे त्योहारों से जुड़े सांस्कृतिक मूल्यों और पर्यावरण की सुरक्षा, दोनों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण को दर्शाता है. उन्होंने सभी दिल्लीवासियों से अपील की कि वे जिम्मेदारी के साथ दिवाली मनाएं, केवल प्रमाणित ग्रीन पटाखे जलाएं और निर्धारित समय का पालन करें. उन्होंने कहा, यह दिवाली केवल रोशनी और मिठाइयों के लिए नहीं, बल्कि दिल्ली की सामूहिक जिम्मेदारी और अनुशासन की मिसाल बनेगी.

पटाखा कारोबारियों के लिए चुनौती, पर उम्मीद कायम

चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन बृजेश गोयल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह दिवाली व्यापार जगत के लिए राहत लेकर आई है. हालांकि उन्होंने यह भी बताया कि समय की कमी के कारण कारोबारियों को कई प्रशासनिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. गोयल ने कहा, दिल्ली में करीब 185 स्थायी पटाखा लाइसेंस धारक कारोबारी हैं, जिनके लाइसेंस पिछले कुछ वर्षों से निलंबित थे अब उन्हें एक्सप्लोजिव विभाग, डीएम, फायर और पुलिस प्रशासन से नए सिरे से अनुमति लेनी होगी. यह प्रक्रिया एक ही दिन में पूरी होनी चाहिए ताकि कारोबारियों को दिवाली से पहले राहत मिल सके. उन्होंने यह भी बताया कि चूंकि दिल्ली में पटाखा निर्माण पिछले कई सालों से बंद है, इसलिए कारोबारियों को बाहर से पटाखे मंगवाने होंगे. सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला न केवल व्यापारियों के लिए राहत का संदेश है, बल्कि यह उन लाखों लोगों के लिए भी खुशी की बात है जो परंपरा को पर्यावरण के साथ संतुलित रूप से निभाना चाहते हैं. अब यह जिम्मेदारी दिल्लीवासियों की है कि वे नियमों का पालन करते हुए ग्रीन दिवाली मनाएं ताकि खुशियों का यह पर्व रौशनी और पटाखों की गूंज के साथ इकोफ्रेंडली तरीके से मनाया जा सके.

जीएसटी समायोजन से नहीं होगी ट्रंप के टैरिफ़ की काट

प्रभात पटनायक

भारत के खिलाफ ट्रंप के टैरिफ हमले का भारतीय अर्थव्यवस्था पर संकुचनकारी प्रभाव पड़ेगा में कोई संदेह नहीं है। अगर ट्रंप इस समय लगाये जा रहे 50 फीसद की दर से अपने टैरिफ को कम भी कर देता है, तब भी यह भारत के अमेरिकी माल पर टैरिफ घटाए जाने के बदले में ही किया जा रहा होगा। ऐसा खासतौर पर उसके कृषि उत्पादों तथा दुग्ध उत्पादों पर टैरिफ घटाए जाने के बदले में ही किया जा रहा होगा, जिसका मतलब होगा अमेरिका से आयात का बढ़ना और इसलिए भारत में आमदनियों का घट जाना। ट्रंप के टैरिफ के इस संकुचनकारी प्रभाव की काट करने के लिए जरूरत इसकी होगी कि भारतीय अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त क्रय शक्ति डाली जाए और इसके तीन संभव रूप हो सकते हैं। पहला, राजकोषीय घाटे का बढ़ाया जाना। दूसरा, अमीरों पर ज्यादा कर लगाने के जरिए बढ़े हुए सरकारी खर्च के लिए वित्त व्यवस्था किया जाना, जो अमीरों की बचत वाली उनके गैर-व्यय के एक हिस्से को, सरकारी खर्चों में तब्दील कर रहा होगा। या तीसरा, ऋण की वित्त व्यवस्था से संचालित, निजी उपभोग व्यय में बढ़ोतरी या उसी हिसाब से निजी बचत अनुपात में कमी। गुड्स एंड सर्विसेज कर की दरों में, 22 सितंबर से लागू हुए जिन समायोजनों की घोषणा की गयी थी, वह अपने आप में अर्थव्यवस्था में कोई क्रय शक्ति नहीं डालते हैं। इस तरह का समायोजन, जो पहले की चार कर दरों 5, 12, 18 तथा 28 फीसद की जगह पर सिर्फ दो दरें, 5 तथा 18 फीसद करता है (यह चंद ''कलंकित मालों'' के अलावा है, जिन पर अब 40 फीसद की दंडात्मक दर लागू होगी), निश्चित रूप से उपभोक्ताओं पर कुल बोझ घटाने का काम करेगा, बशर्ते ये रियायतें उन तक ''पहुंचायी जाएं''। इसके साथ ही, अगर इससे होने वाली सरकार के राजस्व की हानि की भरपाई, खर्च में उसी हिसाब से कटौती कर के की जाती है, न कि राजकोषीय घाटे के आकार में बढ़ोतरी से, तो इस कदम के जरिए अर्थव्यवस्था में क्रय शक्ति में कोई शुद्ध बढ़ोतरी नहीं हो रही होगी। उसी सूरत में तो कर रियायतों के बल पर निजी उपभोग में जितनी बढ़ोतरी होगी, सरकारी खर्चों में उतनी ही कटौती हो जाएगी और इस तरह सकल मांग के स्तर में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही होगी। इसलिए, इस तरह के हालात में जीएसटी कर में दी गयी रियायतें, अर्थव्यवस्था पर डोनाल्ड ट्रंप द्वारा थोपे गए सकल मांग के संकुचन की काट नहीं कर सकती हैं। इतना ही नहीं, इस सूरत में इसका तो दावा किया ही नहीं जा सकता है कि जीएसटी की दरों के घटाए जाने से, मेहनतकश जनता का कुल उपभोग बढ़ जाएगा, जिसका सरकार दावा कर रही है। अगर, उन क्षेत्रों में जिनमें इस तरह की रियायतों से उपभोग बढ़ने जा रहा है, मजदूरी-आमदनियों का हिस्सा उतना ही है, जितना उन क्षेत्रों में है, जिनमें राजस्व हानि के चलते सरकारी खर्चों में कटौतियां की जाने वाली है, तो मजदूरों का कुल उपभोग (या और सामान्य रूप से मेहनतकशों का कुल उपभोग), सरकार के राजकोषीय कदमों के चलते अपरिवर्तित ही रहेगा। और यह किसी भी तरह से असंभव पूर्व-कल्पना नहीं है क्योंकि सरकार के खर्चों में कटौतियां मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्र में होंगी, जिसका निर्माण क्षेत्र एक बड़ा घटक है। और निर्माण बहुत ही श्रम सघन होता है, जिसमें कुल उत्पाद में मजदूरी-आय का हिस्सा, उसी हिसाब से ज्यादा होता है। इसका अर्थ यह है कि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मेहनतकश जनता की आमदनियों में जो कटौती थोपी जा रही है, उसकी काट सरकार के राजकोषीय कदमों से मेहनतकशों की आमदनियों में किसी भी बढ़ोतरी से नहीं होने वाली है। सरकार के राजकोषीय कदम उनकी आमदनियों को जहां का तहां, उस निचले स्तर पर ही छोड़ देंगे, जिस पर ट्रंप के टैरिफ उन्हें धकेल देंगे। संक्षेप में यह कि ट्रंप के टैरिफों से भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे संकुचनकारी प्रभावों की काट करने के लिए और इन टैरिफ के चलते मेहनतकश जनता की आय में होने वाले संकुचन को निष्प्रभावी बनाने के लिए, मोदी सरकार से कुछ भी किया ही नहीं है। हालांकि, ऐसा लग सकता है कि जीएसटी रियायतें देना, मेहनतकश जनता के उपभोग में बढ़ोतरी करने के बराबर है, लेकिन जब तक राजकोषीय घाटा बढ़ाया नहीं जाता है (या इसके विकल्प के तौर पर अमीरों से और ज्यादा प्रत्यक्ष कर इकट्ठा करने के जरिए, इस तरह की जीएसटी रियायतों से होने वाली राजस्व हानि की भरपाई नहीं की जाती है), तब तक सरकार के इन राजकोषीय कदमों से मेहनतकश जनता का कुल उपभोग वास्तव में अपरिवर्तित ही बना रहेगा। जहां भारतीय अर्थव्यवस्था पर ट्रंप के टैरिफ के संकुचनकारी प्रभावों की मोदी सरकार के राजकोषीय कदमों से तो शायद ही कोई काट हो रही होगी, निजी उपभोक्ता खर्चों में ऐसी बढ़ोतरी का क्या जो ऋण से संचालित हो सकती है या बचत अनुपात में कटौती से संचालित हो सकती है? अखबार इसकी खबरों से भरे हुए हैं कि जीएसटी की दरों में समायोजन से, सरकार को अनुमानतः कितनी राजस्व हानि होने जा रही है। खुद केंद्र सरकार ने एक पूरे साल में राजस्व हानि का आंकड़ा 48,000 करोड़ रुपये लगाया है। यह इस पूर्वकल्पना पर आधारित है कि जीएसटी की दरों में कमी से कुल 93,000 करोड़ रुपये की राजस्व हानि होने जा रही है, जिसमें से 45,000 करोड़ रुपये की भरपाई ''कलंकित मालों'' पर कर की दरों में होने वाली बढ़ोतरी से हो जाएगी।

दूसरी ओर, भारतीय स्टेट बैंक ने पूरे साल का घाटा 3,700 करोड़ रुपये ही लगाया है। इस अनुमान का आधार यह है कि जीएसटी दरों में कटौतियों के चलते कीमतों में गिरावट से उपभोग को इतना ज्यादा उत्प्रेरण मिलेगा कि कर की दरों में कटौती के बावजूद, कुल राजस्व में बहुत मामूली गिरावट ही हो रही होगी। बहरहाल, विभिन्न निजी अनुमानों में, और इसमें क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के अनुमान भी शामिल हैं, जीएसटी दरों में कटौती से राजस्व हानि को कहीं कहीं ज्यादा, 1.2 से 1.5 लाख करोड़ रुपये तक आंका है। बहरहाल, इन अनुमानों के पीछे जो सैद्धांतिक पूर्वकल्पनाएं काम कर रही हैं, उन्हें कभी उजागर ही नहीं किया जाता है, जबकि उन्हें उजागर किया जाना चाहिए। यह दावा कि इन कर कटौतियों से उपभोग खर्चों में इतनी जबर्दस्त बढ़ोतरी होगी कि राजस्व हानि मामूली ही होगी (क्योंकि अब कर की घटी हुई दर, कहीं बढ़ी हुई मात्रा पर लागू की जा रही होगी) असली सवाल से कतराकर निकल जाता है। सवाल यह है कि इस बढ़े हुए उपभोग के लिए क्रय शक्ति आएगी कहां से? अगर बेस लेवल उपभोग पर कर रियायतें, मान लीजिए कि 100 रुपये की दी जा रही हैं, तो बेस लेवल से ऊपर उपभोग में 100 रुपये की बढ़ोतरी स्वतः रूप से समझ में आती है। लेकिन, उस सूरत में राजस्व घाटा 100 रुपये का होगा, इससे एक पैसा कम का नहीं। लेकिन, अगर दावा यह किया जा रहा है कि बेस लेवल पर उपभोग खर्च में 100 रुपये की कर रियायत के चलते 200 रुपये बढ़ोतरी हो जाएगी, जिससे राजस्व का वास्तविक नुकसान बेस लेवल उपभोग पर कर रियायतों से घटकर होगा, तो सवाल यह खड़ा होता है कि 100 रुपये की यह अतिरिक्त क्रय शक्ति आएगी कहां से? यह तर्क दिया जा सकता है कि इन कर रियायतों से उपभोक्ताओं में ऐसा जोश पैदा होगा कि वे उपभोग बढ़ाने के लिए ऋण लेंगे या फिर इसके लिए अपनी बचत में हाथ डालेंगे। बहरहाल, हम एक क्षण के लिए इसे सच भी मान लें, तब भी यह तथ्य तो अपनी जगह रहता है कि मजदूर वर्ग को न तो इस तरह के ऋणों का पात्र समझा जाएगा और न उनके पास ऐसी बचत होगी, जिसमें से पैसा निकाल कर, टिकाऊ उपभोक्ता मालों की कीमतों में कमी का फायदा उठा सकें। दूसरे शब्दों में उपभोग में तथाकथित उछाल, मजदूर वर्ग के बीच से आने की उम्मीद तो की नहीं जा सकती है। मध्यवर्गीय उपभोक्ता, जिनमें वेतनभोगी भी शामिल हैं, यह देखकर कि कर रियायतों के चलते चीजें अचानक पहले से कुछ सस्ती हो गयी हैं, ऋण लेने के बल पर या अपनी बचतों में हाथ डालने के सहारे, शायद पहले से ज्यादा खरीदारी करने के लिए, तैयार हो जाएं। लेकिन, उस सूरत में भी उपभोग में यह उछाल अस्थायी ही होगी।

सम्पादकीय...

जबरन धर्म परिवर्तन

पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिन्दू और सिख परिवारों की लड़कियों के साथ दुष्कर्म के बाद उनके धर्म परिवर्तन के मामलों में निरन्तर बढ़ोतरी होती देखी जा रही है, जो कि बेहद चिन्ता का विषय है। हाल ही में पाकिस्तान के सिन्ध प्रान्त में एक हिन्दू परिवार की 15 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ पहले दुष्कर्म किया गया और बाद में जबरन इस्लाम कबूल करवा उसका निकाह एक बुजुर्ग के साथ कर दिया गया। पीड़िता के द्वारा घर वापसी के लिए लगातार गुहार लगाई जा रही है। इससे कुछ दिन पूर्व ही इसी तरह का एक मामला 9 वर्षीय लड़की के साथ हुआ और जब उसके परिवार वाले उसे अस्पताल ले जा रहे थे तो उन पर जानलेवा हमला भी किया गया। इससे पहले भी कई हिन्दू और सिख बच्चियां इन लोगों की हैवानियत का शिकार बन चुकी हैं। इस मामले को भारत की सरकार को गंभीरता से लेते हुए इस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाकर एक्शन करवाना चाहिए, अगर मुगलिया इतिहास को देखा जाए तो इस तरह से महिलाओं पर अत्याचार मुगल काल में अक्सर होता रहा है। उस समय तो हिन्दू महिलाओं को जबरन उठाकर ले जाया जाता और टके-टके में बकायदा मंडियों में जैसे सामान बेचा जाता है उस प्रकार लड़कियों की मंडिया लगाकर उन्हें बेचा जाता, मगर बाद में गुरु गोबिंद सिंह जी के सजाए हुए खालसे ने इनके खिलाफ आवाज उठाई और हिन्दू लड़कियों को इनकी कैद से छुड़वाकर घर वापस भेजा गया इस प्रकार इनके अत्याचार पर लगाम लगी, मगर आज ऐसा प्रतीत होता है कि इन्हीं के वंशज हो हैं जो इस प्रकार से हिन्दू और सिख लड़कियों पर पुनः अत्याचार कर जबरन उनका धर्म परिवर्तन करवाने पर अमादा हुए हैं, वैसे देखा जाए तो इस्लाम धर्म भी इस बात की इजाजत नहीं देता कि किसी महिला के साथ और वह भी नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया जाए जिससे ऐसा लगता है कि जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें अपने धर्म के प्रति जानकारी का आभाव है। पाकिस्तान में भी इन्हीं के धर्म से कुछ लोग हैं जो इस सब के विरुद्ध आवाज उठाते हैं और उन्हीं के माध्यम से पता चलता है कि पिछले कुछ सालों में एक हजार से अधिक हिन्दू सिख लड़कियां इनका शिकार बन चुकी हैं। भारत में भी लव जेहाद के मामले सामने आ रहे हैं जिसमें इन लोगों के द्वारा हिन्दू सिख लड़कियों को गुमराह कर अपने जाल में फंसाया जाता है, उनकी जिन्दगी से खिलवाड़ कर या तो उन्हें छोड़ दिया जाता है या फिर उनका धर्म परिवर्तन करवा दिया जाता है, हालांकि भारत की सरकार और समाज सेवी संस्थाओं की चौकसी के चलते यह लोग अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। गुरु हरगोबिन्द जी ने 52 हिन्दू राजाओं को मुक्ति दिलाई थी - इतिहास में इस बात का जिक्र है कि सिखों के छठे गुरु हरिगोबिंद साहिब जी ने ग्वालियर के किले में कैद 52 हिन्दू राजाओं को आजाद करवाया था। बात उस समय की है जब गुरु हरगोबिन्द साहिब जी को बादशाह के द्वारा कैद कर ग्वालियर के किले में रखा गया जहां पहले से ही 52 हिन्दू राजा कैद कर रखे गए थे पर जैसे ही बादशाह को गुरु जी की शक्तियों के बारे में जानकारी मिली तो उसने उनकी रिहाई का आदेश दिया मगर गुरु जी ने रिहाई लेने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि उनके साथ सभी कैद हिन्दू राजाओं को भी रिहा किया जाए, जिस पर बादशाह ने गुरु जी के सामने किले से रिहाई के समय शर्त रखी कि जो भी राजा गुरु जी को पकड़कर बाहर आ जाएगा उसे भी गुरुजी के संग रिहा कर दिया जाएगा गुरु जी ने शर्तानुसार 52 कलियों वाला कुर्ता सिलवाया जिसकी एक-एक कली पकड़कर सभी 52 हिन्दू राजा भी जहांगीर की कैद से रिहा हो गए। कैद से बाहर आकर जब गुरु जी अमृतसर की धरती पर पहुंचे तो सिखों ने पूरे शहर को दीप जलाकर रोशन किया तभी से सिख धर्म के लोग इस दिन को बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाते हुए अपने घरों में दीये जलाते हैं। यह दिन दीवाली के दिन ही आता है इसलिए सिख दीवाली वाले दिन को बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाते हैं। समाज सेवी दविन्दरपाल सिंह पप्पू का मानना है कि गुरु साहिब चाहते तो अकेले बादशाह जहांगीर की कैद से रिहा हो सकते थे, मगर उन्होंने अपने साथ दूसरे राजाओं को भी कैद मुक्ति करवाकर एक सन्देश समूची मानवता को दिया उसी प्रकार सिख जत्थेबंदियों को भी चाहिए कि गुरु साहिब के दिखाए मार्ग पर चलते हुए कौम की बेहतरी के लिए एकजुटता दिखाएं। न्यूयार्क में गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर सड़क : गुरु तेग बहादुर जी जिन्होंने मानवता की एक ऐसी मिसाल कायम की और दूसरे धर्म की रक्षा हेतु अपने प्राणों की आहूती दे दी जो कि संसार में और कहीं भी देखने को नहीं मिलती कि कोई शख्स स्वयं अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए आगे आया हो। उनकी शहादत को 350 साल हो चुके है और आज संसारभर में उनकी याद को लोग अपने अपने अंदाज में मनाते हुए दिख रहे हैं। सिख जत्थेबंदियों और धार्मिक कमेटियों के द्वारा तो शताब्दी पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं, मगर गुरु जी की शहादत को केन्द्र और राज्यों की सरकारों के द्वारा सरकारी स्तर पर मनाने की तैयारियां की जा रही है। जिसे देखकर अब विदेशों में भी गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी शताब्दी पर वहां की सरकारों के द्वारा भी कुछ न कुछ ऐसा किया जा रहा है जो कि एक यादगार बनकर रहेगा। न्यूयॉर्क सिटी के क्वींस क्षेत्र में 114वीं स्ट्रीट और 101वीं एवेन्यू के चौराहे का आधिकारिक रूप से नामकरण गुरु तेग बहादुर जी वे के नाम से किया गया है। यह पहला अवसर है जब भारत के बाहर किसी स्थान ने नौवें सिख गुरु के सम्मान में इस प्रकार की श्रद्धांजलि दी है। यह पहल सिख नेताओं और समुदाय के सदस्यों के नेतृत्व में की गई है, जो गुरु तेग बहादुर जी की अमर विरासत का उत्सव मनाती है। वह विरासत जो धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा, मानव अधिकारों की सुरक्षा और न्याय के पक्ष में अडिग खड़े रहने का प्रतीक है। विदेशी लोग भी इस बात को मानने लगे हैं। दरबार साहिब जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रिहाइश की समस्या पिछले कुछ सालों में देश ही नहीं विदेश की संगत बड़ी संख्या में श्री दरबार साहिब के दर्शनों के लिए काफी बढ़ने के चलते हालात ऐसे बन चुके हैं कि रोजाना हजारों की गिनती में श्रद्धालुगण पहुंचते हैं और उनके लिए सबसे बड़ी समस्या रिहाइश की आती है, हालांकि शिरोमणि कमेटी द्वारा निरंतर नई रिहाइश बनाई भी जा रही हैं अनेक होटल भी हैं, मगर बावजूद इसके संगत को अक्सर परेशानी का सामना करना पड़ता है। दिल्ली के राजौरी गार्डन गुरुद्वारा साहिब के अध्यक्ष हरमनजीत सिंह जो कि शिरोमणि कमेटी सदस्य भी हैं उनका मानना है कि बड़ी सिंह सभाओं को इस ओर ध्यान देते हुए दरबार साहिब के नजदीक जगह लेकर सराय का निर्माण करवाना चाहिए। राजौरी गार्डन की कमेटी ने तो इसकी शुरुआत कर दी है। इससे पूर्व पीतमपुरा गुरुद्वारा द्वारा भी सराय बनाई गई है, अगर इसी प्रकार अन्य सिंह सभाएं भी आगे आकर इस कार्य को करें तो निश्चित तौर पर कुछ हद तक राहत संगत को दी जा सकती है खासकर दिल्ली की संगत को इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा और वह अपनी सिंह सभा में संपर्क कर रिहाइश ले सकेंगे।

'अपने देश वापस जाओ'

यह एक ऐसी जघन्य घटना थी जिसने इंग्लैंड में रह रहे भारतीय समुदाय को झकझोर कर रख दिया। बर्मिंघम में ओल्डबरी में एक ब्रिटिश सिख महिला के साथ दो गोरों द्वारा बलात्कार किया गया, बेरहमी से मारपीट की गई, और जाते-जाते बलात्कारी यह संदेश दे गए कि 'वह यहां की नहीं है' और उसे अपने देश लौट जाना चाहिए। अर्थात् मामला केवल बलात्कार का ही नहीं था उस महिला को उसकी नस्ल के लिए टार्गेट किया गया, क्योंकि वह सिख है। महिला को निशाना बनाकर उसके बाकी समुदाय को संदेश भेजा जा रहा है कि तुम यहां सुरक्षित नहीं हो। कुछ दिन पहले पास के एक शहर में दो बुजुर्ग सिख टैक्सी चालकों पर हमले हो चुके हैं। ब्राडकास्टर नरेन्द्र कौर ने राजनेता और मीडिया को इस ज़हर फैलाने में संलिप्त बताते हुए कहा है कि, आप रोजाना नस्लवाद के जानवर को खाना खिला कर जब ऐसा कुछ हो जाए तो सदमे का ढोंग नहीं कर सकते। चिन्ता की बात यह है कि ऐसी नस्ली घटनाओं के समाचार कई पश्चिमी देशों से आ रहे हैं। हमारे लोगों को बताया जा रहा है कि उन्हें वहां पसंद नहीं किया जा रहा। जब से 'गुड फ्रैंड' डोनाल्ड ट्रम्प सत्तारूढ़ हुए हैं, भारतीयों के प्रति द्वेष उनकी सड़कों पर उतर आया है। हमारे धार्मिक स्थलों पर हमले बढ़ गए हैं। जिसे 'हेट क्राइम' अर्थात् नफ़रत की अपराध, की घटनाएं बराबर बढ़ रही हैं। उनका सोशल मीडिया यह कह कर हिंसा को उकसा रहा है कि यह विदेशी हमारी नौकरियां छीन रहे हैं। इन देशों की हालत क्या है यह गौर करने की बहुत ज़रूरत है, अमेरिका: अमेरिका में भारतीय समुदाय को अति सफल समझा जाता है। मैक्सिको के नागरिकों के बाद सबसे बड़ा अप्रवासी समुदाय भारतीय है। अमेरिका की जनसंख्या का 1-1.5 फीसदी भारतीय समुदाय, आयकर में 5-6फीसदी का योगदान डालता है। प्रति परिवार भारतीयों की वार्षिक 126000-145000 डालर की आमदनी राष्ट्रीय आय से दो गुना है। बड़ी-बड़ी कम्पनियों के सीईओ भारतीय मूल के हैं। अमेरिका में 9-10 फीसदी डाक्टर भारतीय मूल के हैं। ईर्ष्या बढ़ रही है। ट्रम्प 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' के नारे को लेकर चल रहे हैं, वहां नस्ली घटनाओं के समाचार लगातार मिल रहे हैं। एक प्रकार से हमें बताया जा रहा है कि हमारी वहां ज़रूरत नहीं है चाहे यह आभास भी है कि भारतीयों के बिना गुजारा नहीं। कनाडा- टोरंटो में अप्रवासियों के खिलाफ प्रदर्शन हो चुका है। वहां 'कैनेडा फर्स्ट' रैली निकल चुकी है। कैनेडा फर्स्ट रैली के आयोजकों का कहना है कि लाखों लोग विदेशों से आ रहे हैं जिससे उनके संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। जब ट्रूडो प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने दरवाजे खोल दिए थे। कथित खालिस्तानियों को उत्पात मचाने का मौका दे दिया था। इससे हिंसा भी बढ़ी थी। स्थानीय नागरिक अप्रवासियों के प्रवेश पर रोक लगाना चाहते हैं। शिकायत है कि अप्रवासियों के कारण उनके लिए नौकरियों से लेकर आवास कम पड़ रहे हैं। हमारे बहुत नौजवान क़ानून का पालन नहीं करते। गैंगस्टर भी पैदा हो गए हैं। आस्ट्रेलिया- पहली बार आस्ट्रेलिया के बड़े शहरों में आव्रजन के खिलाफ रैलियां निकाली गईं। सिडनी, मेलबर्न आदि शहरों में हजारों लोग इसमें शामिल हुए। रैलियों के लिए निकाले गए विज्ञापनों में भारतीय मूल के लोगों को विशेष तौर पर टार्गेट किया गया। भारतीयों की वहां आबादी 3.1फीसदी है पर यह भी बर्दाश्त नहीं हो रही। बड़ी संख्या में विद्यार्थी भी हैं जिनके बल पर उनके कालेज और विश्वविद्यालय चल रहे हैं। आस्ट्रेलिया की सरकार ने इन रैलियों की निंदा की है और कहा है कि यह लोग नव-नाजियों से जुड़े है, पर हकीकत है कि लोग अप्रवासियों को पसंद नहीं करते। जैसे एक आदमी ने कहा है कि इतने लोग अंदर आ गए है कि हमारे लोगों को घर नहीं मिलते, असपतालों में जगह नहीं है और सड़कें कम पड़ रही है।

इंग्लैंड -13 सितंबर को लंदन में आधुनिक काल की बड़ी रैलियों में से एक देखी गई जब दस से पन्द्रह लाख लोगों ने केन्द्रीय लंदन में 'युनाइट द किंगडम' नाम से अप्रवासी विरोधी रैली निकाली। इंग्लैंड के हिसाब से यह बहुत बड़ी रैली थी और लंदन पुलिस भी इसकी विशालता देख कर दंग रह गई। इनके नेता टॉमी रोबिनसन, जो जेल काट चुका है, के अनुसार यह देश में सांस्कृतिक क्रान्ति की शुरूआत है। इंग्लैंड में नस्ली भावना सदा से है पर यह पहली बार है कि उसका सार्वजनिक प्रदर्शन किया जा रहा है। उनकी शिकायत है कि अप्रवासियों के कारण उनके घरों, नौकरियों और सेवाओं पर दबाव पड़ रहा है। नारा था 'हम अपना देश वापिस चाहते हैं'। आयरलैंड - नस्लवाद इतना फैल चुका है कि आयरलैंड जैसे देश में जहां पहले ऐसी घटनाओं के बारे सुना भी नहीं जाता था, भारतीयों पर हमले हो रहे है। डब्लिन में एक सिख ड्राइवर को पिटाई वाला वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला गया कि, 'अपने देश वापस जाओ'। वहां छह साल की लड़की को 8-14 वर्ष के लड़कों ने पीट डाला। उनका भी संदेश था कि 'वापस अपने देश इंडिया जाओ'। ऐसी घटनाएं इतनी बढ़ गई है कि हमारे दूतावास को एडवाइजरी जारी करनी पड़ी कि बाहर जाते समय सावधानी बरतें। सोशल मीडिया में प्रवासी विरोधी प्रचार बहुत चल रहा है। पश्चिमी देशों में अप्रवासी विरोधी भावना जो दबी हुई थी वह ट्रम्प के आने के बाद बेलगाम हो रही है। उनका राष्ट्रवाद अब 'दूसरे' के प्रति नफ़रत पर आधारित है। बड़ा कारण पुरातन समय से चली आ रही ईर्ष्या की भावना है। हमारी सफलता के कारण हम से नफ़रत हो रही है। 'रा' के पूर्व प्रमुख विक्रम सूद के अनुसार वहां, नफ़रत और डर है कि एक दिन यह इंडियनज़ उनसे आगे निकल जाएंगे, इसलिए जरूरी है कि इन्हें सांस्कृतिक और नस्ली तौर पर दबाया जाए। आखिर हमारे लोग बुद्धिमान है, मेहनती है, अंग्रेजी जानते है, प्रशिक्षित है। मौका मिलने पर वह किसी का भी मुकाबला कर सकते हैं, इसीलिए दूसरे अप्रवासी समुदायों से अधिक हमें नापसंद किया जा रहा है, क्योंकि हमसे अधिक ख़तरा महसूस किया जा रहा है। हमारे अपने देश में अभी मौकों की कमी है इसलिए लोग बाहर भाग रहे है अब यह दरवाज़ा कानूनी तौर पर या गैर कानूनी तौर पर शारीरिक हिंसा के द्वारा बंद करने की कोशिश हो रही है। हमारे बारे अभी तक वही पुरानी साम्राज्यवादी सोच थी कि यह रूढ़िवादी, पिछड़ा, सपेरों और हाथियों का देश है। हमें कभी गोरों के बराबर नहीं समझा गया।

आखिर चर्चिल ने हमारी आज़ादी के समय कहा था कि यह 'तिनकों से बने लोग है। कुछ ही वर्षों में इनका नामोनिशान मिट जाएगा'। आज वही देश सबसे तेज गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है और चर्चिल के देश को पीछे छोड़ आया है। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बड़े व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत का दौरा कर हटे हैं। उन्हें हमारा निवेश चाहिए ताकि वहां नौकरियां बढ़ सकें। विज्ञान में, टैक में, अंतरिक्ष साइंस में, मेडिसिन में, यहां तक कि वहां की राजनीति में हमारे लोग बढ़ रहे हैं। ऋषि सुनक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। कमला हैरिस माने व माने, पर हैं तो वह भी भारतीय मूल की। आयरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री लियो वाडकर का परिवार गोवा से है। काश पटेल अमेरिका में एफबीआई के प्रमुख हैं। अमेरिका की सिलिकन वैली हमारे लोगों ने बसाई है। अमेरिका की कस्टमर सर्विस की 70व कॉल भारत भेजी जाती हैं। पर भारतीयों के बढ़ते कदमों को पसंद नहीं किया जा रहा। आखिर हम गोरों की श्रेणी में तो आते नहीं पर उनसे अधिक सफल हैं। न ही हम पिछड़े अश्वेत हैं जिनको नजरंदाज़ किया जा सकता है। हमारा धर्म और खाना-पीना उन्हें समझ नहीं आता। हमारी संस्कृति को वह पसंद नहीं करते। उनके लिए यह मानना मुश्किल है कि जिन मूर्ति पूजकों का वह मज़ाक़ उड़ाते थे वह उनसे अधिक समझदार और प्रतिभाशाली हो सकते हैं। सॉनफ्रैंसिस्को में रहने वाली लेखिका सावित्री मुमुक्षु ने लिखा है, शताब्दियों से उन्होंने जो साम्राज्यवादी फंतासी पाल रखी थी, को टेक्नोलॉजी, बिसनेस और वैश्विक प्रभाव में नेतृत्व कर हिन्दुओं ने मिटा दिया है। इस कथन में कुछ अतिश्योक्ति हो सकती है पर यह हकीकत है कि दुनिया हमारे उत्थान को देख रही है, कुछ दिलचस्पी से, कुछ हैरानी से तो कुछ पूर्ण नफ़रत से।

पश्चिम के देशों में जो अप्रिय स्थिति बन रही है उसका सामना करने के लिए हमें तैयार रहना होगा। हमारे विदेश विभाग को सक्रियता से अपने लोगों की सहायता के लिए आगे आना चाहिए। इस समय यह सक्रियता केवल बयान दागने तक सीमित लगती है।

अमेरिका में जो हालत बन रहे है उसके बारे वहां रह रहे भारतीय समुदाय की खामोशी भी चुभ रही है। जो मोदी-ट्रम्प की कथित दोस्ती के कसीदे पढ़ते थे और जिन्हें मोदी ने 'राष्ट्र दूत' कहा था, अचानक खामोश पड़ गए हैं, जो प्रभावशाली जगह पर भी हैं, चाहे सरकार में हो या संसद में हो या टॉप कम्पनियों में हो, उनकी आवाज़ नहीं निकल रही। हम चाहते हैं कि वह अच्छा जीवन व्यतीत करें पर वह ज्यादती के खिलाफ आवाज़ तो उठा सकते हैं। पूर्व राजदूत नवतेज सरना ने लिखा है, जब भी वहां कोई भारतीय नाम उभरता है तो हमें उछलना नहीं चाहिए। उनके लिए हवन करने की कोई ज़रूरत नहीं। न ही अपने गांवों में इनके अंकल या आंट ढूंढने की ज़रूरत है। आखिर में इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं। न ही इनकी 'फ्रैंडशिप' के कोई मायने है। यह सबक हमें ज़बरदस्ती सिखाया जा रहा है।

बिहार - गठबन्धन की राजनीति

बिहार के मतदाता पूरे देश में राजनैतिक रूप से सर्वाधिक सजग मतदाता माने जाते हैं। इसके कुछ ऐतिहासिक व सांस्कृतिक कारण भी हैं परन्तु वर्तमान में इस राज्य में पिछले तीस वर्षों से जिस प्रकार की राजनीति हो रही है उसमें जातिवाद ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर लिया है मगर इसके बावजूद 2005 और 2010 के विधानसभा चुनावों में हमें देखने को मिला कि लोगों ने जाति-धर्म को तिलांजिली देकर अपने मत का प्रयोग किया और अपनी मनमर्जी की सरकारों का गठन किया। निश्चित रूप से इन दोनों ही चुनावों में बिहार की जनता की पहली पसन्द वर्तमान मुख्यमन्त्री श्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जद (यू) रही। वास्तव में यह जनादेश बिहार को जातिवादी राजनीति से उबारने के लिए था। परन्तु क्या इसमें नीतीश बाबू सफल रहे ? इसका उत्तर हमें नकारात्मक मिलता है क्योंकि इस दौरान नीतीश बाबू ने जाति के आधार पर ही अपना नया वोट बैंक तैयार कर लिया जिसे अति पिछड़ा वोट बैंक कहा जाता है। सवाल यह है कि बिहार में जिन लालू प्रसाद यादव को 1990 में भारी धूम-धड़ाके के साथ स्व. देवीलाल ने मुख्यमन्त्री बनाया था उन्होंने अपने राजनीतिक मसीहा स्व. चौधरी चरण सिंह के ग्रामीण वोट बैंक को जातिगत आधार पर बांट डाला और मुस्लिम-यादव वोट बैंक बना डाला। उनके इस कार्य को स्व. रामविलास पासवान ने भी आगे बढ़ाया और एकजुट ग्रामीण मतदाताओं को दलित-मुस्लिम वोट बैंक में बांट डाला। नीतीश बाबू भी इस काम में पीछे नहीं रहे और महादलित के नाम पर अति पिछड़ा व मुस्लिम वोट बैंक बना डाला। इसकी वजह से बिहार में राष्ट्रीय पार्टियों कांग्रेस व भाजपा की महत्ता समाप्त सी होती चली गई जिसके कारण से इन्हें अन्ततः क्षेत्रीय दलों की शरण में जाना पड़ा। लालू प्रसाद ने इस काम में होशियारी दिखाई और उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया और एक जमाने के कांग्रेस के वोट बैंक को ही अपनी पूंजी बना डाला दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने भाजपा का दामन थामा और उसके सीमित शहरी जातियों के वोट बैंक के साथ अपना वोट बैंक मिलाकर चुनाव जीतना शुरू किया। बिहार में भाजपा की खास पकड़ शुरू से ही नहीं रही अतः उसे नीतीश के रूप में अपना विस्तार करने का अवलम्ब मिला। इसकी वजह यह रही कि राज्य की राजनीति में पहले कम्युनिस्टों व बाद में समाजवादियों का प्रभुत्व बढ़ने से साम्प्रदायिक राजनीति का दायरा बहुत सीमित रहा। जनसंघ या भाजपा के विस्तार के लिए बहुत जरूरी था कि उसे नीतीश बाबू जैसे किसी जनाधार वाले नेता का अवलम्ब मिले। यह कार्य भाजपा ने बहुत चतुरता के साथ किया और श्री रामविलास पासवान के जीवित रहते ही 2014 के लोकसभा चुनावों से पूर्व उनकी लोक जनशक्ति पार्टी के साथ भी गठबन्धन किया। यह लोकसभा चुनाव नीतीश बाबू ने अकेले अपनी पार्टी जद(यू) के बूते ही लड़ा और उन्हें भारी पराजय का मुंह देखना पड़ा।

इससे यह साबित हो गया कि नीतीश बाबू की अकेले दम पर ताकत इतनी नहीं है कि वह बिहार में बहुमत प्राप्त कर सकें। अतः 2015 के विधानसभा चुनावों में उन्होंने लालू प्रसाद की पार्टी राजद के साथ गठबन्धन किया और बहुमत प्राप्त करके भाजपा को 243 सदस्य वाली विधानसभा में 52 पर समेट दिया। उस समय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी की लोकप्रियता अपने चरम पर थी। इससे एक बात साफ हो गई कि बिहार में यदि समूचा ग्रामीण वोट बैंक संयुक्त तरीके से एकजुट हो जाये तो वह किसी भी सीमा तक सफलता प्राप्त कर सकता है। हालांकि स्व. पासवान की पार्टी तब 2015 के चुनाव में भाजपा के साथ ही थी। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि बिहार में आज भी हार-जीत का फैसला यह आबादी ही करती है जिसकी जनसंख्या 86 प्रतिशत है। इसमें 63 प्रतिशत मतदाता पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के हैं और 23 प्रतिशत के लगभग अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के हैं। भाजपा की चतुरता और कुशलता यह है कि वह इन वर्गों के बीच ऐसे राजनीतिक गठबन्धन बनाती है जिससे इन वर्गों का बहुत बड़ा हिस्सा उसके पक्ष में आ जाये। राज्य में जो एनडीए गठबन्धन है वह इसका जीता-जागता प्रमाण है क्योंकि इसमें नीतीश कुमार के अलावा जीतन राम मांझी, चिराग पासवान व उपेन्द्र कुशवाहा भी शामिल हैं। इन सभी दलों की अकेले-अकेले शक्ति इतनी नहीं है कि वे अपने बूते पर विधानसभा सीटें जीत सकें। दूसरी तरफ लालू प्रसाद की पार्टी राजद का जो गठबन्धन है उसका गणित थोड़ा भिन्न है क्योंकि इसके साथ राज्य के अल्पसंख्यक या मुस्लिम मतदाता एक मुश्त रूप से हैं और पिछड़े वर्ग व अति पिछड़े भी हैं। इसके गठबन्धन में वामपंथी दल भी शामिल हैं जिनका वोट बैंक भी अति दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़े हैं। इसके साथ ही मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी भी है जिसके साथ अति पिछड़ों का एक समुदाय है। इस प्रकार देखें तो दोनों ही गठबन्धन सिर्फ ग्रामीण वोट बैंक पर ही खेल रहे हैं और उसे जातियों में बांटकर अपना बहुमत लाना चाहते हैं। ऐसे माहौल में भाजपा या कांग्रेस की भूमिका बहुत सीमित हो जाती है। यही वजह रही कि बिहार में नीतीश बाबू की पार्टी जद(यू) को एनडीए में बड़ा भाई कहा जाता था। मगर वर्तमान विधानसभा चुनावों में यह भूमिका भाजपा के पास चली गई है और उसने जद(यू) को अपने बराबर 101 सीटें ही लड़ने के लिए दी हैं। इसके साथ ही भाजपा यह हुंकार नहीं भर रही है कि चुनावों के बाद एनडीए के मुख्यमन्त्री नीतीश कुमार ही होंगे। दूसरी तरफ लालू के इंडिया गठबन्धन में भी कमोबेश हालत यही है क्योंकि कांग्रेस भी आवाज नहीं दे रही है कि गठबन्धन के बाद राजद के श्री तेजस्वी यादव ही मुख्यमन्त्री होंगे। दोनों ही गठबन्धन भावी मुख्यमन्त्री का चेहरा खुलकर सामने नहीं ला रहे हैं। इसकी वजह से दोनों ही गठबन्धनों में सीट बंटवारे को लेकर तरह-तरह के विवाद जन्म ले रहे हैं और पनप रहे हैं। मगर अब पहले चरण के नामांकन के लिए केवल दो दिन का समय शेष रह गया है अतः हमें देखने को मिल सकता है कि एक सीट पर कहीं-कहीं कई-कई उम्मीदवार पर्चा दाखिल करते हुए मिलें। परन्तु इससे चुनाव की जरूरत इसलिए नहीं है कि बिहार के मतदाता उड़ती चिड़िया को भी हल्दी लगाने में माहिर होते हैं।

महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर के बाद बिहार- राहुल गांधी इंडिया गठबंधन को संभाल क्यों नहीं पा रहे हैं?

2024 के लोकसभा चुनाव में सहयोगी दलों की मदद से कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी। तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लड़ने के लिए राहुल गांधी ने उस यूपीए के नाम को भी त्याग दिया जिसके बैनर तले कांग्रेस ने वर्ष 2004 से 2014 तक देश में राज किया था। लोकसभा चुनाव से पहले यूपीए की जगह पर राहुल गांधी ने सहयोगी दलों के साथ मिलकर एक नया मोर्चा बनाया जिसे इंडिया गठबंधन का नाम दिया गया। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद सहयोगी दलों के समर्थन के बल पर नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री तो बन गए लेकिन भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार किसी गठबंधन को इतनी ज्यादा सीटें दिलाने का श्रेय लेकर कांग्रेस ने राहुल गांधी को सर्वमान्य नेता के तौर पर स्थापित करने का प्रयास किया। कुछ हद तक कांग्रेस को अपने इस अभियान में कामयाबी मिलती भी दिखाई दी। वोट चोरी का अभियान चला कर और बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाल कर राहुल गांधी अपने आपको विपक्षी इंडिया गठबंधन के नेता के तौर पर स्थापित करने में थोड़े बहुत कामयाब होते भी दिखाई दिए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा मुखिया अखिलेश यादव से लेकर तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री एवं डीएमके सुप्रीमो स्टालिन तक से उनके व्यक्तिगत संबंध मजबूत होते नजर आए। जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव जीतने में राहुल गांधी और नेशनल कांफ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला की व्यक्तिगत केमिस्ट्री का जबरदस्त योगदान माना जाता है। बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने तो खुलकर राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार तक बता दिया। लेकिन इन सबके बावजूद अचानक देश की राजनीति तेजी से बदलती हुई नजर आने लगी है। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा सीट और विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और नेशनल कांफ्रेंस आमने-सामने आ गए हैं। जम्मू कश्मीर से राज्यसभा सांसदों के लिए होने वाले चुनाव में उमर अब्दुल्ला की पार्टी ने तीनों सेफ सीट पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं और कांग्रेस को जो चौथी सीट ऑफर की है, उसे जीतना बहुत मुश्किल है। कांग्रेस पहले से ही इसे लेकर अपने सहयोगी दल से नाराज चल रही है क्योंकि अब विधानसभा की जिन 2 सीटों पर उपचुनाव होना है, उसे लेकर भी मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर विधानसभा की 2 सीटों- बडगाम और नगरोटा में 11 नवंबर को चुनाव होना है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष तारिक हामिद कर्रा ने [illegible] पर गठबंधन के सिद्धांतों का अनादर करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि वह राज्यसभा की एक सेफ सीट देने के अपने वादे से मुकर गई। कांग्रेस ने गठबंधन धर्म की याद दिलाते हुए सख्त शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा है कि या तो नेशनल कांफ्रेंस उन्हें विधानसभा की एक सीट दे या फिर कांग्रेस दोनों ही सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार देगी। महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव के समय से ही शुरू हुई खटपट अब तक कम होने का नाम नहीं ले रही है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर और दुनिया भर में भेजे गए सांसदों के प्रतिनिधिमंडल को लेकर एसपी और कांग्रेस के सुर अलग-अलग ही नजर आ रहे हैं।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने वन्दना ऑफसेट प्रिंटर्स, ए-9, साउथ पीरागढ़ी एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2011/00862)

वृद्धा आश्रम में जाकर छात्रों ने देखा अपनों से दूर अपनों की दुनिया

जेपी एजुकेशन अकादमी के बच्चों ने की वृद्धाश्रम में बुजुर्गों की सेवा

आनंदनगर, महराजगंज।

बृहस्पतिवार को जेपी एजुकेशन अकादमी, महदेवा के छात्र/छात्राओं ने फरेंदा सथिति आधारशिला वृद्धाश्रम में पहूंच कर बुजुर्गों की सेवा की। उनके मनोभाव के अनुसार उन्हें बात चीत की और उनका आशीर्वाद लिया। सामाजिक उत्तरदायित्व और सेवा भाव से लैश छात्र छात्राओं ने वृद्धाश्रम का भ्रमण किया और यह जानने की पूरी कोशिश की अपनों से दूर रहकर भी एक ऐसी दुनिया है जहां अपनों से प्यार मिलता है । अपनों से अधिक मनोभाव से देख भाल करने वाले लोग होते हैं। बच्चों ने वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्गों को फल, बिस्किट आदि वितरित किए तथा उनके साथ समय बिताया। बच्चों ने बुजुर्गों से बातचीत कर उनके जीवन के अनुभव सुनें और उनके प्रति सम्मान तथा स्नेह प्रकट किया। वृद्धजन भी बच्चों के इस स्नेहिल व्यवहार से अत्यंत प्रसन्न हुए। विद्यालय के प्रधानाचार्य आनन्द शंकर श्रीवास्तव ने बताया कि ऐसे कार्यक्रमों से बच्चों में संवेदना, करुणा और सेवा की भावना का विकास होता है। विद्यालय परिवार ने यह संकल्प लिया कि भविष्य में भी ऐसे सामाजिक कार्य नियमित रूप से किए जाते रहेंगे ताकि विद्यार्थियों में मानवीय मूल्यों का विकास हो सके। कार्यक्रम में आर्या त्रिपाठी, सोनी यादव, दीपलक्ष्मी, लक्ष्मी श्रीवास्तव, खुशी, साक्षी, सौम्या, श्रद्धा, रिया, अम्बिका, प्रियांशी, अमन, अभिषेक, सौरभ, आशीष, शिवनाथ, देवेंद्र, कृष्णा, सुमित, सूरज, अर्पण आदि छात्र/ छात्राओं ने भाग लिया। इस अवसर पर विद्यालय के एडमिन हेड शशी श्रीवास्तव, अरविंद श्रीवास्तव, उमेश साहनी, अमित श्रीवास्तव, किशन श्रीवास्तव, सत्यप्रकाश, शरदेन्दु मिश्र, आलोक श्रीवास्तव, अमित सिंह, , संतोष शर्मा आदि शिक्षकगण छात्रों के मार्गदर्शन हेतु उपस्थित रहे।

प्रभात की 386 वीं काव्य गोष्ठी सम्पन्न

कप्तानगंज (कुशीनगर) ।

नगर की साहित्य सामाजिक व सांस्कृतिक संस्था प्रभात साहित्य सेवा समिति की मासिक काव्य गोष्ठी स्वर्गीय सुदामा देवी कॉम्प्लेक्स बेचू बीए के आवास पर संपन्न हुई अध्यक्षता इंद्रजीत इंद्र ने व संचालन बेचू बीए ने किया। गोष्ठी के मुख्य अतिथि शंभू सजल व विशिष्ट अतिथि शिक्षक व पत्रकार दिनेश यादव रहे । सर्वप्रथम मां शारदे के चित्र पर अतिथियों द्वारा पुष्पार्चन करने के बाद मां शारदे की वंदना से विनोद गुप्ता ने प्रारंभ किया । इसके अलावा नात पाक अर्शी बस्तवी ने पढ़ा । तदोपरांत बेनी गोपाल शर्मा ने यह पढ़ा हमें डर नहीं लगता तीर और तलवारों से , हमें डर नहीं लगता गोरी जैसे हथियारों से इसके बाद विनोद गुप्ता ने खूब सुनाया- उठ कर गिरना गिर कर उठना जीवन की रीत यही, नजरों से गिरकर उठ जाना है इतना आसान नहीं इसके बाद कन्हैया लाल करुण ने यह सुनाया- अपनी जीत को ही ना सर्वोपरि कहिए, सबको ध्यान में रख परस्पर मिल रहिये। इसके बाद डॉक्टर इम्तियाज समर ने यह सुनाया- कहीं खुलूस कहीं दोस्ती कहीं पे वफा, दिलो दिमाग में हिंदुस्तान रखते है वरिष्ठ कवि गीतकार शंभू सजल ने यह पढ़ा -बेनकाब एक दिन कोई महफिल में था,उस घड़ी सूरज बड़ी मुश्किल में था। अर्शी बस्तवी ने खूब सुनाया - आप अपने ख्यालों में उलझे रहे मेरी दुनिया इधर से उधर हो गई। बेचू बीए ने यह गीत सुनाया- मैं चीखना चाहती तो हूं, लेकिन ये काले बादल। अध्यक्षता कर रहे इंद्रजीत इंद्र ने यह सुना कर वह वही लूटी -दुनिया में इनसे बेहतर इंसान नहीं है, उनकी दुआ से बढ़कर वरदान नहीं है। कर कर के उनकी सेवा अपनी बिगड़ी बना ले, मां-बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं है। इस मौके पर शिवकुमार रौनियार,सोनू गलाई वाले, कृष्णा मधेशिया, अमित यादव, इस्लाम, अरविंद आदि मौजूद रहे।

मां बाप से बढ़ कर कोई भगवान नहीं है..

डीएम की अध्यक्षता में विकास कार्यों की हुई समीक्षा बैठक

कुशीनगर।

जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने बताया कि सीएम डैशबोर्ड पर प्राप्त प्रगति रिपोर्ट के अनुसार कुशीनगर जनपद ने प्रदेश में 10वीं रैंक प्राप्त की है,जो प्रशंसनीय उपलब्धि है। उन्होंने इसके लिए सभी अधिकारियों को बधाई दी और कहा कि इसी प्रकार टीम भावना से कार्य करते हुए अगले मूल्यांकन में और बेहतर रैंक हासिल की जाए। उन्होंने कहा कि जिन विभागों के कार्य 'सी' एवं 'डी' श्रेणी में हैं, वे तत्काल सुधारात्मक कदम उठाएं। कार्यों में लापरवाही किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

सांसद देवरिया सहित जनपद कुशीनगर के आला अधिकारियों ने रॉकेट लॉन्चिंग प्रतियोगिता स्थल का किया निरीक्षण

कुशीनगर।

सांसद देवरिया शशांक मणि त्रिपाठी ,जिलाधिकारी कुशीनगर महेंद्र सिंह तंवर ,मुख्य विकास अधिकारी गुंजन द्विवेदी, एवं पुलिस अधीक्षक कुशीनगर केशव कुमार नें जनपद कुशीनगर के थाना सेवरही क्षेत्रान्तर्गत रॉकेट लॉन्चिंग प्रतियोगिता के दृष्टिगतस्थालीय निरीक्षण किया। थाना सेवरही क्षेत्रांतर्गत जीरो बंधा के पास, ग्राम जंगली पट्टी (रकबा जंगल पट्टी सेवरही) में स्थित नरायणी नदी के तट पर, 27, 28 और 29 अक्टूबर 2025 को होने वाले राष्ट्रीय स्तर की 'IN-SPACe CANSAT और मॉडल रॉकेट्री इंडिया स्टूडेंट कॉम्पिटिशन 2024-25 की तैयारियों के दृष्टिगत सांसद देवरिया श्री त्रिपाठी, जिलाधिकारी कुशीनगर श्री तंवर, पुलिस अधीक्षक श्री कुमार, मुख्य विकास अधिकारी श्रीमती द्विवेदी के साथ ही इसरो टीम द्वारा संबंधित स्थल का निरीक्षण किया गया। यह प्रतियोगिता भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO), इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर (IN-SPACe) तथा एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया (ASI) के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हो रही है, जिसका उद्देश्य पूरे देश के स्नातक छात्रों को मॉडल रॉकेट्री, CANSAT (कैन-सैटेलाइट) प्रणालियों के डिजाइन, निर्माण और लॉन्चिंग में व्यावहारिक अनुभव प्रदान करना है। इस प्रतियोगिता में 700-800 से अधिक छात्र भाग लेंगे, जो अपने स्वयं के बनाए गए 100 से ज्यादा मॉडल रॉकेट्स और पेलोड्स को लॉन्च करेंगे, तथा यह भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। निरीक्षण का आयोजन स्थल की उपयुक्तता, सुरक्षा मानकों, संचार प्रणालियों, रिकवरी व्यवस्थाओं तथा पर्यावरणीय प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए किया गया।

जमीन विवाद में मारपीट, चार घायल- एक जिला अस्पताल रेफर

नेबुआ नौरंगिया, कुशीनगर।

हनुमानगंज थाना क्षेत्र के नरकहवा गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। इस घटनामें चार लोग घायल हो गए, जिनमें से एक को गंभीरचोटों के कारण जिला अस्पताल रेफर किया गया हैयह विवाद खड्डा तहसील क्षेत्र के छोटका नरकहवा टोलामें गाटा संख्या 217 की 7 डिस्मिल जमीन पर कब्जेऔर निर्माण को लेकर करीब दो साल से चल रहा था।

चकबंदी अधिकारी द्वारा पहले भी नापी कराई गई थी,लेकिन एक पक्ष इससे सहमत नहीं था। भुवाल चौहान लगातार एसडीएम खड्डा चकबंदी अधिकारी और डीएमसे नापी कर कब्जे वाली भूमि पर निम्माण की मांग कररहे थे। चकबंदी विभाग की टीम ने जमीन कीश्रदोबारा नापी की। जब भुवाल चौहान ने बांस काटे, तो दूसरा पक्ष नाराज हो गया और विवाद बढ़ गया। इसके बाद दोनों पक्षों में लाठी-डंडों से मारपीट शुरू हो गई।मारपीट में एक पक्ष से भागीरथी चौहान (33) और सुदामा चौहान (30) घायल हुए, जबकि दूसरे पक्ष से? बिकाऊ यादव और एक महिला को चोटें आईं।सूचना मिलने पर हनुमानगंज पुलिस मौके पर पहुंचीऔर सभी घायलों को सीएचसी तुर्कहा भेजा। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने भागीरथी चौहान कोगंभीर चोट के कारण जिला अस्पताल रेफर कर दिया,जहा उनका इलाज जारी है।भुवाल चौहान ने पांच लोगों के खिलाफ धारदार हथियार से जानलेवा हमला करने का आरोप लगाते हुए हनुमानगंज पुलिस को तहरीर दी है।इस संबंध में एसएचओ हनुमानगंज संजय कुमार ने बताया कि एक पक्ष की तहरीर मिल गई है, जबकि दूसरेपक्ष की तहरीर अभी नहीं मिली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

वार्षिक सम्मेलन में पदाधिकारी का हुआ चयन कप्तानगंज को प्रथम स्थान

कप्तानगंज (कुशीनगर) । कस्बे के रमा टेक्निकल कॉलेज में वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया जिसमें पदाधिकारी के चयन और मेधावियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों से डायरेक्टर व छात्रों ने भाग लिया जिसमें अच्छा प्रदर्शन करने वाले संस्था के डायरेक्टर को मेडल व शिल्ड देकर सम्मानित किया गया वहीं छात्रों को प्रोत्साहन के रूप में प्रमाण पत्र दिए गए। समारोह के दौरान राजगोपाल मिश्रा को रमा टेक्निकल उत्तर प्रदेश का चीफ डायरेक्टर, श्रवण सिंह को मध्य प्रदेश व जीरहमान को बिहार का के डायरेक्टर नामित किया गया। इस दौरान सर्वोच्च शाखा मे प्रथम स्थान कप्तानगंज रमा टेक्निकल डिग्री कॉलेज, गोंडा द्वितीय व बस्ती को तिसरा स्थान मिला। टॉप 10 शाखा में गौरा चौकी प्रथम सिकरीगंज द्वितीय डुमरियागंज को तीसरा स्थान मिला। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कप्तानगंज रमा टेक्निकल कॉलेज के डायरेक्टर राजगोपाल मिश्रा ने कहा कि संगठन ने जिम्मेदारी का जो भार मुझे दिया है उसका इमानदारी से पालन करूंगा।हर छात्र को अच्छी शिक्षा प्रदान करना मेरी जिम्मेदारी है। जब तक छात्र को तकनीकी शिक्षा नहीं मिलेगी तब तक उसका विकास नहीं हो सकता। आज समाज में तकनीकी शिक्षा की अति आवश्यकता है जिस पर सभी युवाओं को पहल करना होगा। इस दौरान अर्चना मिश्रा, धर्मराज, प्रमोद कुमार,आदित्य कुशवाहा, अनीता,नंदनी कुशवाहा,आकृति मिश्रा, आदि मौजूद रहीं।

सेमरा हरदो न्याय पंचायत ब्लॉक चैंपियन , धर्मपुर बुजुर्ग को द्वितीय स्थान

कुशीनगर ।

उच्च प्राथमिक विद्यालय मोतीललहा में आयोजित 29 वीं दो दिवसीय ब्लाक स्तरीय बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन गुरुवार की सायं विजेता खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र व मेडल वितरण के साथ हुआ। व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धाओं में प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त तथा टीम प्रतिस्पर्धाओं में विजेता टीम आगामी जिला स्तरीय बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता में ब्लाक का प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रतियोगिता में सेमरा हरदो ब्लॉक चैंपियन व धर्मपुर बुजुर्ग दूसरे स्थान पर रहा । प्रतियोगिता में उच्च प्राथमिक स्तर बालिका वर्ग मे 100 मीटर दौड़ में धर्मपुर बुजुर्ग संध्या प्रथम व देवरिया पांडेय की अनीता दूसरे स्थान पर, 200 मी बालिका वर्ग में धर्मपुर बुजुर्ग की पूजा प्रथम व हरैया बुजुर्ग की फरीदा द्वितीय, 400 मीटर के दौड़ में धर्मपुर बुजुर्ग की पूजा प्रथम व देवरिया पांडे की आंचल राजभर द्वितीय, 600 मीटर की दौड़ में धर्मपुर बुजुर्ग की संध्या प्रथम वह देवरिया पांडे की आंचल राजभर द्वितीय स्थान पर रही। श्रुतलेख में सेमरा हरदो की अंतिम

गुप्ता प्रथम व बलूचहा की प्रगति दुबे दूसरे स्थान पर रही मानचित्र प्रतियोगिता में सेमरा हरदो की नेहा गुप्ता प्रथम व बेलवा जंगल की नेहा कुशवाहा दूसरे स्थान पर रही। बालक वर्ग 100 मीटर की दौड़ में बेलवा जंगल के मेराज प्रथम व मोतीललहा के करन द्वितीय , 200 मीटर की दौड़ में हरैया बुजुर्ग के कुंदन प्रथम व मोतीललहा के गुलशन द्वितीय, 400 मीटर की दौड़ में धर्मपुर बुजुर्ग के अमन प्रथम व हरैया बुजुर्ग के अमित द्वितीय स्थान पर रहे। पुरस्कार वितरण समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते बीएसए डॉ राम जियावन मौर्य ने कहा कि खेल सफलता के लिए अवसर प्रदान करते हैं। बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता में सफल छात्रों की प्रतिभा यह साबित करती है कि वह संसाधन की मोहताज नहीं है। पुरस्कार प्रतिभागी को और बेहतर करने की प्रेरणा देते हैं। जिलास्तरीय प्रतियोगिता ने प्रतिभाओं को निखरने का अवसर दिया है।बीईओ सुरेंद्र बहादुर सिंह ने आभार व्यक्त करते हुए सफल

- आगामी जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता में भाग लेंगे सफल खिलाड़ी - सफलता के लिए अवसर प्रदान करते हैं खेल : बीएसए

खिलाड़ी व टीमों को जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता के लिए अग्रिम शुभकामना दी। संचालन रवींद्र नारायण पांडेय व शिवानंद मिश्र ने संयुक्त रुप से किया। इस दौरान जिला व्यायाम शिक्षक अनिल मिश्र, जूशिसं के जिला उपाध्यक्ष इंद्रजीत मणि त्रिपाठी, मंत्री कुंजेश्वर सिंह, राशैसं के जिला उपाध्यक्ष दिलीप पांडेय, अमरदीप शुक्ला, अनूप सिंह, संजय सिंह, मेहरुद्दीन अली, देवेंद्र मिश्र, राकेश पांडेय, राकेश यादव, पीताम्बर यादव, अनुपम त्रिपाठी, अरविंद मद्धेशिया, राजकुमार भास्कर, गीता चतुर्वेदी, शिवकुमार पांडेय, चंद्र प्रकाश दुबे, आलोक श्रीवास्तव, सुनील पांडेय, परशुराम तिवारी, आदित्य सिंह, मारकंडे प्रसाद व बृजकिशोर मिश्र आदि उपस्थित रहे।

अबकी बार पर्यावरण संग उत्सव, सात साल बाद दिल्ली के लोगों को आतिशबाजी की मिली अनुमति

नई दिल्ली। दिल्ली के लोग करीब सात साल बाद दीपावली पर पटाखे जला पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति मिलने के बाद दिल्लीवासी बेहद खुश हैं। इससे उत्साहित दिल्ली सरकार ने इसके लिए कोर्ट का धन्यवाद किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि ये निर्णय देश की सांस्कृतिक संवेदनाओं और जनभावनाओं को समझने वाला कदम है, जो परंपरा और पर्यावरण संरक्षण दोनों के बीच सुंदर संतुलन स्थापित करता है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता बेहद खराब स्तर पर पहुंचने के कारण राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), दिल्ली सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने साल 2015-16 से ही पटाखों पर नियंत्रण लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार दिल्ली एनसीआर में पारंपरिक पटाखों की बिक्री और उपयोग पर अस्थायी रोक लगाई। अदालत ने यह माना कि पटाखे प्रदूषण के मुख्य कारणों में से एक हैं। इनके प्रयोग पर सख्त नियंत्रण जरूरी है। तब से दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध रहा। इस साल सुप्रीम कोर्ट ने दीपावली पर 19 और 20 अक्टूबर को सुबह 6 से 7 बजे और रात को 8 से 10 बजे तक ग्रीन पटाखे जलाने की सशर्त छूट दी है। दिल्ली सरकार की ओर से अधिकृत विक्रेता ही ग्रीन पटाखे बेचेंगे। फिलहाल सरकार ने साफ किया है कि अभी उसने किसी को भी ग्रीन पटाखे बेचने की अनुमति नहीं दी है। जल्द ही विश्वसनीय और सक्षम विक्रेताओं को अधिकृत लाइसेंस दिया जाएगा। इसके लिए बुधवार शाम को मंत्री ने दिल्ली के तमाम पटाखा दुकानदारों के साथ बैठक की थी। बुधवार को सचिवालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि सरकार ज्यादातर दुकानदारों को लाइसेंस देगी, ताकि ग्रीन पटाखों की कालाबाजारी न हो। सबको आसानी से पटाखे उपलब्ध हों। दिल्ली पुलिस, एमसीडी, डीपीसीसी, सीएक्यूएम सहित दिल्ली सरकार की अन्य जिम्मेदार एजेंसियां ग्रीन पटाखों की बिक्री, इन्हें जलाने के समय, कोर्ट के निर्देशों का पालन कराएंगी। उन्होंने दिल्लीवासियों से सरकार के साथ मिलकर नियमों का पालन करने में सहयोग करने की अपील भी की है। मंत्री ने कहा है कि लोगों के सहयोग से दीपावली के पर दिल्ली की हवा बेहतर रही तो ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति आगे भी जारी रहेगी। दिल्ली सरकार ने साफ निर्देश दिए हैं कि केवल नीरी की ओर से प्रमाणित क्यूआर कोड लगे ग्रीन पटाखे ही दुकानदार बेच पाएंगे। इनकी बिक्री 18 से 20 अक्टूबर तक तीन दिन तक की जा सकेगी। ग्रीन पटाखों की बिक्री के स्थान और बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस जिलाधिकारी और पुलिस उपायुक्त जल्द ही तय करेंगे। सभी जिलों में अधिक दुकानों को लाइसेंस दिए जाएंगे। दिल्ली में ग्रीन पटाखे जलाने की सुप्रीम कोर्ट से छूट मिलने के बाद पर्यावरण मंत्री ने डिविजनल कमिश्नर नीरज सेमवाल, दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त रविंद्र यादव, डीपीसीसी के चेयरमैन संदीप कुमार और पीईएसओ, नीरी, एमसीडी और एनडीएमसी और संबंधित एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और कोर्ट के दिशा निर्देशों को लागू करने की तैयारी की।

मोदी सरकार का अपराधियों को अल्टीमेटम, शाह बोले- एक भी भगोड़ा बच नहीं पाएगा

नई दिल्ली।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को नई दिल्ली में भगोड़ों का प्रत्यर्पण चुनौतियाँ और रणनीतियाँ विषय पर आयोजित सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम का आयोजन केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) ने किया था। शाह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक अभियानों, मजबूत समन्वय और स्मार्ट कूटनीति को एक साथ लाना है। उन्होंने कहा कि आज, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, एक मजबूत भारत सुरक्षित सीमाओं के साथ-साथ कानून का शासन सुनिश्चित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस सम्मेलन में, हम वैश्विक अभियानों, मजबूत समन्वय और स्मार्ट कूटनीति को एक साथ लाना सुनिश्चित करेंगे। अमित शाह ने न केवल देश के अंदर, बल्कि सीमा पार भी आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने पर जोर दिया। शाह ने इस बात पर जोर दिया कि गंभीर अपराध करने के बाद देश छोड़कर भागने वाले अपराधियों को वापस लाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, हमें न केवल भारत में भ्रष्टाचार, अपराध और आतंकवाद के विरुद्ध, बल्कि सीमा पार बैठे अपराधियों के विरुद्ध भी शून्य सहनशीलता की नीति अपनानी होगी। वांछित भगोड़ों को वापस लाने और उन्हें भारतीय कानून व्यवस्था के अनुसार दंडित करने का रास्ता खोजना हमारी जिम्मेदारी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वित्तीय घोटालेबाजों, साइबर अपराधियों, आतंकवादियों और आपराधिक गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध निर्मम दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। शाह ने जोर देकर कहा कि हमें इन अपराधियों के मन में बैठे इस विश्वास को तोड़ना होगा कि भारतीय कानून हम तक नहीं पहुँच सकता... उस विश्वास को तोड़ना हमारी जिम्मेदारी है... हमें उस पारिस्थितिकी तंत्र को भी समाप्त करना होगा जो ऐसे अपराधियों को न्यायिक, वित्तीय और राजनीतिक समर्थन प्रदान करता है। शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं कि कोई भी अपराधी कानून की पकड़ से बच न पाए।

इससे पहले 14 अक्टूबर को, अमित शाह ने घोषणा की थी कि भारत का प्रमुख आतंकवाद-रोधी बल, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी), जल्द ही उत्तर प्रदेश के अयोध्या में अपना सातवाँ ऑपरेशनल हब स्थापित करेगा, जिससे किसी भी आतंकवादी हमले से निपटने के लिए इसकी देशव्यापी उपस्थिति का विस्तार होगा। यह घोषणा हरियाणा के मानेसर में एनएसजी के 41वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान की गई।

विकास बनाम बुर्का! सीएम योगी बोले- बिहार में घुसपैठियों के वोटों की जुगत में आरजेडी-कांग्रेस

दानापुर।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर सवाल उठाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल (राजद) पर तीखा हमला करते हुए कहा कि महागठबंधन चाहता है कि घुसपैठिए आगामी विधानसभा चुनावों में वोट दें ताकि राज्य के लोगों के अधिकार छीने जा सकें। आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) उम्मीदवार रामकृपाल यादव के समर्थन में दानापुर में एक चुनावी रैली में बोल रहे थे। यह बिहार में आदित्यनाथ की पहली चुनावी रैली थी। आदित्यनाथ ने कहा कि राजद, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) गठबंधन अब बुर्के पर राजनीति कर रहे हैं। क्या उन्हें (घुसपैठियों को) बिहार में वोट देने दिया जाना चाहिए? क्या उन्हें बिहार के लोगों के अधिकार छीनने दिए जाने चाहिए? उन्होंने आगे कहा कि राजद और कांग्रेस चुनावों में पारदर्शिता के खिलाफ हैं। अपने संबोधन में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी सराहना की और कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार ने राज्य का कायाकल्प कर दिया है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन वाली सरकार राज्य के विकास के लिए लगातार काम कर रही है और अब बिहार में विकास को कोई नहीं रोक सकता। योगी ने कहा कि 1990 से 2005 तक बिहार के जंगलराज और वंशवादी राजनीति के बारे में कौन नहीं जानता। आपने देखा होगा कि वो कौन लोग थे जिन्होंने बिहार को आध्यात्मिक ज्ञान की धरती को वंशवादी राजनीति और अपराध की धरती में बदल दिया, हमारे युवाओं के लिए पहचान का संकट पैदा कर दिया। विकास के नाम पर यहाँ कैसे अराजकता फैलाई गई, ये किसी से छिपा नहीं है.. इसलिए, पिछले 20 वर्षों में एनडीए सरकार ने बिहार को उस कलंक से मुक्त करने के लिए प्रभावी ढंग से काम किया है। आज बिहार में डबल इंजन वाली सरकार, इसे और भी प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का आह्वान करने फिर आई है।

आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश और बिहार के रिश्तों पर भी बात की और इसे साझी विरासत बताया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार का रिश्ता एक आत्मा का बंधन, एक संस्कृति का बंधन और एक संकल्प का बंधन है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लोगों से बिहार में सत्तारूढ़ एनडीए को वोट देने की अपील करते हुए कहा, यह रिश्ता भगवान राम और माता जानकी के बंधन जितना ही अटूट है। बिहार में विधानसभा चुनाव दो चरणों में होने हैं - 6 और 11 नवंबर को। वहीं, मतगणना 14 नवंबर को होगी।

बिहार मतदाता सूची : सुप्रीम कोर्ट ने ईसी को त्रुटियां सुधारने का दिया निर्देश, 4 नवंबर को होगी सुनवाई

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के बहुचर्चित विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से उत्पन्न कानूनी मुद्दों पर सुनवाई के लिए 4 नवंबर की तारीख तय की। कार्यवाही के दौरान, चुनाव आयोग ने अदालत को सूचित किया कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत तैयार अंतिम मतदाता सूची में किसी भी मतदाता का नाम हटाए जाने के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की गई है। पीठ ने आगे कहा कि एक जिम्मेदार संवैधानिक प्राधिकारी होने के नाते, चुनाव आयोग से अपेक्षा की जाती है कि वह बिहार मतदाता सूची में मुद्रण संबंधी त्रुटियों और अन्य गलतियों की जाँच करे और उन्हें दूर करे। शीर्ष अदालत ने आगे कहा कि उसे उम्मीद है कि आगामी चुनावों से पहले, चुनाव आयोग मतदाता सूची की सटीकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सुधारात्मक उपाय करेगा। इससे पहले की सुनवाई में, अदालत ने चुनाव आयोग को एसआईआर प्रक्रिया के बाद अंतिम मतदाता सूची से बाहर किए गए 3.66 लाख मतदाताओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। चुनाव आयोग ने पीठ को बताया कि नए जोड़े गए ज्यादातर नाम पहली बार मतदाता बने लोगों के हैं और जिनके नाम हटाए गए थे, उनमें से किसी ने भी अब तक कोई शिकायत या अपील दायर नहीं की है। चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, 30 सितंबर को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची से पता चला है कि एसआईआर प्रक्रिया के बाद बिहार में मतदाताओं की कुल संख्या लगभग 47 लाख घटकर 7.89 करोड़ से 7.42 करोड़ हो गई। हालाँकि, अंतिम आंकड़े 1 अगस्त को जारी मसौदा सूची से 17.87 लाख मतदाताओं की वृद्धि भी दर्शाते हैं, जिसमें मृत्यु, प्रवास या दोहराव के कारण 65 लाख नाम हटाए गए थे।

गुजरात मंत्रिमंडल में फेरबदल, आज गांधीनगर में शपथ समारोह

पूरी कैबिनेट का इस्तीफा, 16 नए चेहरे लेंगे मंत्री पद की शपथ!

अहमदाबाद। गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाले गुजरात मंत्रिमंडल का विस्तार शुक्रवार को होगा।

वहीं इससे पहले आज राज्य के सभी मंत्रियों ने अपने पदों से इस्तीफा सौंप दिया है। वहीं कैबिनेट विस्तार को लेकर एक वरिष्ठ भाजपा नेता ने पहले बताया था कि आगामी मंत्रिमंडल विस्तार में राज्य को लगभग 10 नए मंत्री मिल सकते हैं, और लगभग आधे मौजूदा मंत्रियों को बदला जा सकता है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मंत्रिमंडल का विस्तार शुक्रवार सुबह 11:30 बजे होगा। वर्तमान गुजरात मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री पटेल सहित 17 मंत्री हैं। आठ कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, जबकि इतने ही राज्य मंत्री (एमओएस) हैं। बता दें कि, 182 सदस्यीय विधानसभा वाले गुजरात में 27 मंत्री या सदन की कुल संख्या का 15 प्रतिशत मंत्री हो सकते हैं। इस महीने की शुरुआत में, गुजरात सरकार में राज्य मंत्री जगदीश विश्वकर्मा, केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल की जगह भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई के नए अध्यक्ष बने।

अमित शाह रात को गुजरात जाएंगे

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह गुरुवार की रात करीब 9 बजे गुजरात पहुंचेंगे। वहीं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शुक्रवार सुबह गुजरात पहुंच रहे हैं। आमतौर पर जब मंत्रिमंडल विस्तार होता है, तो भाजपा आलाकमान के इतने नेता मौजूद नहीं होते, इसलिए सरकार में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं।

कांग्रेस से आए नेताओं को मिल सकता है मंत्रीपद

नए मंत्रिमंडल में 16 में से 7-10 मंत्रियों को ड्रॉप करने और 5-7 मंत्रियों को रिपीट किए जाने की चर्चा है। नए चेहरों में कांग्रेस से आए अर्जुन मोढवाडिया, अल्पेश ठाकोर, सीजे चावड़ा और हार्दिक पटेल को मौका मिल सकता है। सौराष्ट्र से जयेश रादडिया और जीतू वाघानी को मंत्रिमंडल में जगह मिलना तय है। खासकर पाटीदारों और उत्तर गुजरात से ठाकोर समुदाय को तवज्जो दिया जाएगा। इसके अलावा, जिन राज्य मंत्रियों को हटाए जाने की संभावना है, उनमें मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम सोलंकी, पंचायत मंत्री बच्चूभाई खाबर, वन एवं पर्यावरण मंत्री मुकेश पटेल, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री भीखूसिंह परमार और आदिवासी विकास मंत्री कुंवरजी हलपति शामिल हैं।

जैसलमेर बस त्रासदी! राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, मृतकों के परिजनों को 10-25 लाख तक की आर्थिक मदद

जैसलमेर।

राजस्थान के थार रेगिस्तान की चिलचिलाती गर्मी में, जैसलमेर से जोधपुर तक की एक रात भर की यात्रा एक भयावह कब्र में बदल गई। 14 अक्टूबर को, जैसलमेर शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूर थईयात गाँव के पास, परिवारों और बच्चों सहित 57 यात्रियों को ले जा रही एक निजी वातानुकूलित स्लीपर बस में आग लग गई। कुछ ही मिनटों में, वाहन, जो कि पाँच दिन पहले ही एसी से सुसज्जित एक नया चमचमाता हुआ अधिग्रहण था, मौत का जाल बन गया।

इक्कीस लोग, जिनमें तीन बच्चे थे, पहचान से परे जल गए। सोलह अन्य स्थानीय अस्पतालों में गंभीर रूप से जलने से जूझ रहे हैं। भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रासदी में जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया, साथ ही मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपये और घायलों को 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जैसलमेर में दुर्घटना स्थल और जोधपुर के अस्पताल का दौरा करने के लिए तत्पर थे राजस्थान सरकार ने जैसलमेर बस हादसे में जान गंवाने वालों के आश्रितों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। इसके तहत मृतकों के आश्रितों को 10-10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।

आधिकारिक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जैसलमेर बस हादसे के मृतकों के आश्रितों और घायलों के लिए आर्थिक सहायता स्वीकृत की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शोक की इस घड़ी में राज्य सरकार मृतकों के परिजनों के साथ खड़ी है तथा उन्हें पूरी मदद देने और घायलों के हरसंभव उपचार के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इसके तहत मृतकों के आश्रितों को 10-10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। जिन परिवारों में तीन या अधिक लोगों की मृत्यु इस दुर्घटना में हुई है, उन परिवारों को 25-25 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। गंभीर घायलों को 2-2 लाख रुपये एवं अन्य घायलों को 1-1 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। शर्मा ने मुख्यमंत्री सहायता कोष नियमों में शिथिलता देते हुए यह स्वीकृति प्रदान की है। मंगलवार को दोपहर बाद जोधपुर जा रही एक निजी बस में जैसलमेर से रवाना होने के बमुश्किल दस मिनट बाद आग लग गई। देखते ही देखते बस आग का गोला बन गई और 19 यात्री जिंदा जल गए और 16 अन्य गंभीर रूप से झुलस गए। गंभीर रूप से घायलों में से एक ने मंगलवार रात अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। एक अन्य घायल की बुधवार को मौत हो गई।

एअर इंडिया हादसे की हो पारदर्शी जांच, विमान के कैप्टन के पिता की सुप्रीम कोर्ट से गुहार

नई दिल्ली।

जून में हादसे का शिकार हुए एअर इंडिया विमान के पायलट इन कमांड दिवंगत कैप्टन सुमित सभरवाल के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर हादसे की निष्पक्ष, पारदर्शी और तकनीकी रूप से सुदृढ़ जांच की मांग की है। दिवंगत कैप्टन सुमीत सभरवाल जून में अहमदाबाद में हुई एयर इंडिया की दुर्घटना में पायलट-इन-कमांड थे। हादसे में 260 लोग मारे गए थे। उनके पिता ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और मांग की है कि एयर इंडिया बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान की दुर्घटना की सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में निष्पक्ष, पारदर्शी और तकनीकी रूप से सुदृढ़ जांच करवाई जाए।

जदयू की दूसरी लिस्ट जारी, 44 को मिला टिकट; गोपाल मंडल की जगह इन्हें मैदान में उतारा

पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 44 प्रत्याशियों को जगह मिली है। सीएम हाउस के सामने प्रदर्शन करने वाले गोपालपुर के वर्तमान विधायक और जदयू नेता गोपाल मंडल का टिकट काट दिया है। इस बार जदयू ने उनकी जगह बुलो मंडल को उम्मीदवार बनाया है। इस लिस्ट में पिछड़े वर्ग से 37, अतिपिछड़ा 22, सामान्य से 22, अनुसूचित जाति से 15, अल्पसंख्यक से चार, अनुसूचित जनजाति से एक प्रत्याशी शामिल हैं। वहीं कुल 101 प्रत्याशियों में 13 महिला भी हैं। जदयू ने सबसे अधिक कुशवाहा समाज के 13 प्रत्याशी, कुर्मी समाज के 12 प्रत्याशी, राजपूत समाज के 10 प्रत्याशी भूमिहार समाज के 9 प्रत्याशी, यादव और धानुक समाज के आठ प्रत्याशियों को टिकट दिया है। जदयू की दूसरी सूची में मंत्री विजेंद्र यादव, लेशी सिंह, शीला मंडल, कलाधर मंडल, सुमित सिंह समेत कई दिग्गजों के नाम शामिल हैं। वहीं जो सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के खाते में जाने की बात सामने आई थी, वहां भी जदयू ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है। इसमें सबसे प्रमुख कदवा सीट है। यहां से पूर्व सांसद दुलाल चंद गोस्वामी को टिकट दिया गया है। वहीं राजद छोड़कर जदयू में शामिल हुई पूर्व मंत्री राजवल्लभ यादव पत्नी व वर्तमान विधायक विभा देवी को नवादा से टिकट दिया है। वह नवादा से चुनाव लड़ेंगी। इसके अलावा निर्दलीय प्रत्याशी और मंत्री सुमित सिंह को जदयू ने चकाई से टिकट दिया है।

यहाँ से तारीफ़, वहाँ से टैरिफ, जयराम रमेश का पीएम मोदी पर तंज, विदेश नीति पर उठाए सवाल

नई दिल्ली। डोनाल्ड ट्रंप के भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा के दावे पर बढ़ते विवाद के बीच, वरिष्ठ कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने गुरुवार को केंद्र पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कांग्रेस में संचार मामलों के प्रभारी महासचिव रमेश ने एएनआई को बताया कि भारत सरकार द्वारा लिए गए फैसलों की घोषणा राष्ट्रपति ट्रंप ने वाशिंगटन डीसी में की है। यहाँ से तारीफ, वहाँ से टैरिफ। जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद के समक्ष अमेरिकी व्यापार समझौते के बारे में विस्तृत जानकारी देने और यह भी बताने को कहा कि यह अभी तक क्यों नहीं हुआ है। रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि रूस से तेल खरीदने के पीछे की सच्चाई क्या है? अमेरिकी व्यापार समझौता अभी तक क्यों नहीं हुआ है? उन्हें संसद को विश्वास में लेना चाहिए, आम सहमति बनानी चाहिए और बताना चाहिए। हमारी विदेश नीति पूरी तरह विफल रही है। राज्यसभा सांसद ने ट्रंप द्वारा किए गए कई दावों पर प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी पर भी सवाल उठाया, जिनमें व्यापारिक धमकियाँ देकर भारत-पाकिस्तान युद्ध रोकना और यह दावा करना शामिल है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। रमेश ने कहा, राष्ट्रपति ट्रंप 51 बार दावा कर चुके हैं कि व्यापारिक धमकी देकर भारत-पाकिस्तान तनाव को कम करने के लिए वे जिम्मेदार हैं। कल ट्रंप ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से कहा था कि भारत को रूस से तेल नहीं खरीदना चाहिए, और भारत ने उन्हें आश्वासन दिया था कि वह रूस से तेल नहीं खरीदेगा। और प्रधानमंत्री इस पर चुप हैं। अगर ऐसा कोई फैसला लिया गया है, तो प्रधानमंत्री को इसकी घोषणा करनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा, प्रधानमंत्री ट्रंप की तारीफ़ में ट्वीट करते हैं, लेकिन टैरिफ अमेरिका लगाता है। भारत सरकार अपने फैसलों की घोषणा क्यों नहीं करती? कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि वह ट्रंप से डरे हुए हैं। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति के दावे पर आपत्ति जताई और अपनी बात को पुष्ट करने के लिए केंद्र पर कई आरोप लगाए।

सट्टा कांड को लेकर पंजाब पुलिस के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर गिरफ्तार, सीबीआई ने लिया एक्शन

रूपनगर। पंजाब पुलिस के डीआईजी रोपड़ रेंज हर चरण सिंह भुल्लर को सीबीआई ने गिरफ्तार किया गया है। यह गिरफ्तारी सट्टा मामले से जुड़ी बताई जा रहा है। पुलिस की तरफ से अभी इस मामले में कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। हालांकि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार डीआईजी को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया गया है। रोपड़ रेंज के डीआईजी हरचरन सिंह भुल्लर को सीबीआई ने रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। सूत्रों के अनुसार, मंडी गोबिंदगढ़ के एक स्क्रैप कारोबारी ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई। सीबीआई टीम ने भुल्लर को मोहाली से हिरासत में लिया।

बिहार महागठबंधन में सीट बंटवारा बना सिरदर्द : नामांकन करीब, लालू-राहुल के बीच फोन पर हुई बात

नई दिल्ली

। बिहार में पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन दाखिल करने में केवल 26 घंटे शेष हैं, लेकिन महागठबंधन ने अभी तक सीट बंटवारे की घोषणा नहीं की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी नेता राहुल गांधी ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत की। कांग्रेस नेताओं ने राजद प्रमुख लालू यादव से भी बात की। बैठक के दौरान, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने खड़गे और राहुल गांधी से कहा कि गठबंधन में अन्य सहयोगियों को भी शामिल किया जाना चाहिए, जो उनके अनुसार ज्यादा महत्वपूर्ण है। सीट बंटवारे पर अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है, लेकिन राजद और कांग्रेस के कई नेता पहले ही नामांकन पत्र दाखिल कर चुके हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता तेजस्वी यादव ने बुधवार को राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से अपनी सीट जीतने का विश्वास जताया। यहाँ पत्रकारों से बात करते हुए, उन्होंने राज्य में बेरोजगारी दूर करने और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए अपनी पार्टी की प्रतिबद्धता दोहराई। तेजस्वी ने मौजूदा सरकार के प्रति बढ़ते जन असंतोष पर प्रकाश डाला और कहा कि महागठबंधन आगामी विधानसभा चुनावों में जीत हासिल करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि राघोपुर की जनता ने मुझ पर दो बार भरोसा किया है और मुझे विश्वास है कि इस बार भी वे मुझ पर भरोसा करेंगे... आप सभी जानते हैं कि हमारी पार्टी का उद्देश्य राज्य से बेरोजगारी दूर करना और बिहार का फिर से निर्माण करना है... राज्य की जनता यहाँ के भ्रष्टाचार से तंग आ चुकी है और नई शुरुआत चाहती है... हमारा महागठबंधन 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार राज्य में सत्ता परिवर्तन होगा।